A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 13 अप्रैल, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 190, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

बना मधुर मेरा जीवन!
नव नव सुमनों से चुन चुन कर
धूलि, सुरभि, मधुरस, हिम-कण,
मेरे उर की मृदु-कलिका में
भरदे, करदे विकसित मन।

बना मधुर मेरा भाषण!
बंशी-से ही कर दे मेरे
सरल प्राण औ' सरस वचन,
जैसा जैसा मुझको छेड़ें
बोलूँ अधिक मधुर, मोहन;
जो अकर्ण-अहि को भी सहसा
करदे मन्त्र-मुग्ध, नत-फन,
रोम रोम के छिद्रों से मा!
फूटे तेरा राग गहन,
बना मधुर मेरा तन, मन!

- सुमित्रानंदन पंत

प्रसंगवश

सिने संगीत के स्वर्णयुग की अंतिम ध्वजवाहिका का स्वर्गारोहण

श्रद्धांजलि/ आशा भोसले

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।

सुरों की मलिका आशा भोसले का अचानक इस फानी दुनिया से चले जाना भारतीय फिल्म संगीत और पार्श्वगायन के स्वर्ण युग की अंतिम जीवित ध्वजवाहिका का स्वर्गारोहण है। रविवार को उन्होंने 92 वर्ष के सांगीतिक जीवन के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हालांकि उनके चाहने वालों को उम्मीद थी कि आशाजी फिर उसी मस्ती के साथ फिर सुरों के रंग बिखेरेंगी, लेकिन वैसा न हो सका। फिल्म संगीत के महान स्त्री-स्वरों में आशाजी की स्पर्द्धा केवल अपनी बड़ी बहन और गान सरस्वती लता मंगेशकर से रही। हालांकि इन दोनों में श्रेष्ठतम कौन ये बहस पहले अंडा या मुर्गी सी अनंत है। संक्षेप में कहें तो लताजी अगर संगीत की मीरा हैं तो आशाजी राधा। गायन में अपनी रेंज, विविधता और वर्सटेलिटी में तो वो कभी-कभी लताजी को भी पीछे छोड़ती प्रतीत होती हैं। महान संगीतकार अनिल विश्वास ने लता और आशा की अद्भुत तुलना करते हुए कहा था कि लता आत्मा से गाती हैं और आशा शरीर से। लेकिन समग्रता में ये दोनों परस्परपूरक हैं। आत्मा बिना क्या देह और देह बिना क्या आत्मा। लता अगर संगीत की देवी हैं तो आशा संगीत की अप्सरा। दोनों ही आसमान से उतरी हुई ऐसी आवाजें हैं, जो सदियों में पैदा होती हैं। लताजी सादगी, पवित्रता, विनम्रता और दैवी स्वर आभा के सर्वोच्च शिखर का प्रतीक हैं तो आशाजी मानव जीवन के संघर्षों, उतार-चढ़ाव, राग द्वेष, जिजीविषा और श्रेष्ठतम को हासिल करने की अंतहीन जिद का सर्वदा फहराता ध्वजदंड हैं।

आशा भोसले के रूप में हमने, इस देश ने भारतीय फिल्म और सुगम संगीत के सुनहरे दौर की अंतिम जीवित रचयिता और साक्षी खो दिया है। जीवन और संगीत को आशाजी ने हमेशा एक चुनौती के रूप में लिया और हर मोड़ पर उसे पराजित कर दिखाया। निजी जिंदगी में नियति के कई आघात सहने के बाद भी आशा भोसले विजय पताका हमेशा अपने हाथों में थामे दिखीं। लताजी के विपरीत बगावत और प्रयोगधर्मिता उनके स्वभाव का हिस्सा रहा। जीवन में आए तमाम उतार- चढ़ावों का असर उन्होंने अपनी संगीत साधना पर कभी नहीं होने दिया। 91 साल की उम्र में भी आशाजी उसी मस्तानी अदा से मंच पर गाती थीं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। हिंदी सिने और गैर फिल्मी गीतों के अनमोल रत्नों में से कई आशाजी के नाम हैं। वह अपने आप में गायन का स्कूल हैं। सुरों और शब्दों की अदायगी, ठहराव, झटके और परफेक्ट स्वराभिनय के माध्यम से किरदार को साकार करना आशाजी की खूबी है। सिने संगीत का सर्वश्रेष्ठ और कालजयी युगल गीत 'अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं', आशाजी ने मोहम्मद रफी के साथ जिस अंदाज में गाया है, वहां मानो वक्त भी ठहर गया- सा लगता है। भाव और रस कोई सा भी हो, सुरों की शक्ल में आशाजी हर किरदार में अपने बेहतरीन किरदार में नमूदार होती हैं। आवाज पर उनका असाधारण कंट्रोल, सुरों के साथ कभी टेस्ट क्रिकेट तो कभी टी-20 की तरह सहज और पावरफुल बैटिंग करना आशाजी जैसी गायिकाओं के लिए ही संभव था। यूं तो उनके लाजवाब गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन स्वरों के माध्यम से चुहलबाजी, मादकता, अल्हड़पन, दीवानगी, प्रेम, वियोग, मिलन, रूठना, हंसाना, कव्वाली, अर्द्ध शास्त्रीय गायन, गजल गायन, भक्तिभाव, लोकगीत, हर रंग में आशा भोसले हर बार अलग नजर आती हैं। अपने पांच दशक लंबे गायन कॅरियर में उन्होंने 20 भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गाने गाएं। लेकिन कभी घंमड नहीं किया। ये वो दौर था, जहां साधना ही पुरस्कार थी। प्रयोगधर्मिता और नई चुनौतियों की स्वीकारना आशाजी की फितरत थी। फिल्म 'उमराव जान' में आशाजी ने गीत 'ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है' में एक जवान और अलग तरह की पुरअसर आवाज निकाल कर सभी को चौंका दिया था। आशाजी ने करीब साठ सालों तक देश के सभी महान संगीतकारों के लिए गाया। फिर चाहे 'अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाय रे' जैसी ब्याहता बेटी की मार्मिक गुहार हो या फिर 'दम मारो दम' जैसी नशीली आवाज हो। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा जैसी शर्मीली छेड़छाड़ हो अथवा 'मैं जब भी अकेली होती हूं तुम चुपके से आ जाते हो,' सपनीली युवती की भावना हो। 'तोरा मन दर्पण कहलाए' जैसी भक्ति में डूबी प्रार्थना हो या फिर 'बलमा माने ना' जैसी शिकायत हो अथवा 'नन्हें मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है' जैसा बालगीत हो, 'पान खाए सैंया हमारो' जैसे नौटंकी गीत हो अथवा 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, जैसी मनुहार हो। आशाजी हर रंग और रस के साथ सम्बन्धित किरदार से एकाकार होती दिखती हैं। महान संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ आशाजी के गाए लाजवाब गीतों ने तो सिने संगीत के माधुर्य और मस्ती का ऐसा अध्याय रचा है कि जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह क्रांतिकारी संगीतकार और दूसरे पति आर.डी.बर्मन के साथ भी आशाजी ने कई बेमिसाल गीत गाए। केवल राष्ट्रभक्ति गीतों के मामले में दीदी लता मंगेशकर उनसे फिनिश लाइन से आगे जाती दिखती हैं। खास बात यह है कि दोनो बहनों ने जो युगल गीत गाए हैं वो भी डुएट सिंगिंग के बेहतरीन नमूने हैं। यही नहीं मराठी में आशाजी के छोटे भाई और महान संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर ने कई कालजयी गीत गवाए हैं। भारत रत्न छोड़कर आशाजी को अपनी सृजनात्मकता के लिए सभी बड़े पुरस्कार मिले।

मंगेशकर परिवार पर यूं तो सरस्वती का ही हाथ है, भारतीय फिल्म संगीत की वह यकीनन 'फर्स्ट फैमिली' है। ऐसा परिवार जिसमें तकरीबन सभी को संगीत का अमृत कलश जन्मजात मिला हो। ऐसे परिवार में संगीत साधना के साथ संगीत की अघोषित आंतरिक प्रतिस्पर्द्धा भी उतनी ही कठिन और कठोर होती है। ऐसे में जब कभी-कभार लताजी अपनी इस छोटी बहन के किसी गाने को सुनकर सराहना मिलती कि आशा तूने यह गीत मुझसे भी अच्छा गाया है तो मानिए कि श्रेष्ठता के पैमाने अपनी सतह से खुद ऊपर उठ जाते हैं। आज जो पीढ़ी साठ के दशक में है या पचास से ऊपर है, वह इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उसने सिने संगीत के इन महान नक्षत्रों की अनंत सुखदायी चांदनी के बीच जन्म लिया, उस संगीत को भोगा और आजतक उसकी रसवर्षा से उबर नहीं पाए हैं। संभव है कि एआई की पीढ़ी संगीत के आत्मिक दौर को कभी समझ और महसूस न कर पाए। लेकिन आशाजी जैसी महान गायिकाओं ने अपने सुरों के मयूरपंख से रची जो कालजयी स्वरांजलियां विरासत में छोड़ी हैं, वो उनके भौतिक रूप से देवलोकगमन के बाद भी सदैव करोड़ों मनों को आह्लादित करती रहेंगी।

संगीत जगत के लिए बड़ा झटका

'सुरों की मलिका' आशा ताई नहीं रहीं

92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मुंबई (एजेंसी)। संगीत जगत को एक बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों फिल्मों के गीतों को स्वरों से सजाने वाली और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी खास मुकाम हासिल करने वालीं 92 साल की गायिका आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कार्डिएक अरेस्ट और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से शनिवार को ही उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रविवार सुबह से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आशा भोसले के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम पसर गया है।

आज होगा अंतिम संस्कार

जानकारी के मुताबिक सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे लोअर परेल में उनके घर पर ही अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

आशा भोसले के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

- पीएम ने कहा-मुलाकातों की यादें हमेशा संजोकर रखूंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने आशा भोसले के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा उनके साथ हुई मुलाकातों की यादें हमेशा संजोकर रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आशा की असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत की सबसे आइकॉनिक और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं।

आष्टा में 184 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन

बेटियों और बहनों के विकास से ही होगा समग्र विकास संभव : मुख्यमंत्री

- आष्टा में सीएम मोहन यादव, रोड शो किया
- सांदीपनी स्कूल में छात्राओं से किया संवाद

आष्टा (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार दोपहर सीहोर जिले के आष्टा पहुंचे हैं। उन्होंने यहां रोड शो किया। कन्नौद रोड मंडी गेट से शुरू हुए रोड शो का जगह-जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रोड शो सांदीपनी विद्यालय पहुंचा। यहां सीएम ने क्लास में जाकर छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आष्टा में नवनिर्मित सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण कर बालिकाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आष्टा में रोड शो कर जनता का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बेटियों और बहनों के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार नारी सशक्तिकरण का बड़ा कार्य इसी माह होने जा रहा है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संसद की विशेष तीन दिवसीय बैठक 16 अप्रैल से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हमारी सरकार अब तक लाड़ली बहन योजना के माध्यम से बहनों को 55 हजार करोड़ से अधिक राशि दे चुकी है। आज आष्टा से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये अंतरित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मातृ सत्ता की व्यवस्था है। अब प्रदेश में हर माह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को सीहोर जिले के आष्टा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 35 वीं किश्त की राशि 1836 करोड़ रुपये हितग्राही बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित किये।

छात्राओं के लिए तीन शिक्षण संस्थाओं में नई सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आष्टा की छात्राओं के लिए आज विशेष सौगात का दिन है। मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय और कन्या विद्यालय में छात्रावास के साथ कन्या विद्यालय के भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीहोर जिले के आष्टा में आज त्रिवेणी संगम है। आष्टा मां पार्वती नदी की उद्गम स्थली है। यहां के सांदीपनि विद्यालयों में 90 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आए हैं। राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख साइकिलें वितरित कर रही है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूल टॉपर बच्चों को स्कूटी दी जा रही है।

किसान कल्याण को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय लिया। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों के लिए अकेले दो साल में लगभग 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ गया है। गेहूं पर 40 रुपए बोनस देकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की जा रही है। अब गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई कर किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं। सिर्फ 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हैं। अकेले सीहोर में 1 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों की दीदियां हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों की 65 लाख से अधिक बहनें सशक्त हुई हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह के लिए 55 हजार रुपए की राशि दे रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 184 करोड़ की लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इनमें आष्टा एवं जावर में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में पात्र लोगों को हितलाभ भी वितरित किये।

होर्मुज की सफाई शुरू...

युद्धपोत, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात

अमेरिका ने शुरू किया 'हाईटेक ऑपरेशन', सुरक्षा भी बढ़ाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सेना ने इस अहम समुद्री रास्ते में बिछी संभावित बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्नत युद्धपोत, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) के तहत दो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इस ऑपरेशन में शामिल हैं। इनका मुख्य काम समुद्र में छिपी बारूदी सुरंगों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। अमेरिकी सेना के मुताबिक, यह अभियान खास तौर पर उन सुरंगों को हटाने के लिए है जिन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जोड़ा जा रहा है। ये सुरंगें बड़े जहाजों और तेल टैंकरों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं।

ड्रोन से होगी समुद्र की जांच- अमेरिका इस काम के लिए सीधे जहाजों को खतरे में नहीं डाल रहा है। इसके बजाय पानी के अंदर चलने वाले रोबोटिक ड्रोन यानी यूयूवी (अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल) का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन टॉरपीडो के आकार के होते हैं और अपने आप समुद्र में घूमकर हाईटेक सोनार तकनीक से समुद्र की सतह का नक्शा बनाते हैं।

बांग्लादेश में दलित हिंदू पर हमला, ममता बनर्जी पर वार

बंगाल चुनाव के मैदान से सीएम योगी की यूपी पर नजर

लखनऊ (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार एंट्री मारी है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सीएम योगी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर उन्होंने पूरे विपक्ष को घेर लिया है। सीएम योगी ने शनिवार को लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित हुए हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने संबंधित कागजात वितरण के बाद बंगाल के रण में इस मुद्दे को छेड़ा।

सीएम योगी ने यूपी की स्थिति का किया जिक्र

सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में यूपी की स्थिति का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं, बल्कि संतुष्टीकरण है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते। उन्होंने कहा कि यूपी में जितने माफिया थे, सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 13 अप्रैल 2026

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

प्रदेश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है

संेधवा। म.प्र.राज्य में 1 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ हो चुका है लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रदेश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में 40 प्रतिशत षिक्षकों के पद रिक्त हैं। 5 हजार से अधिक स्कूल भवन असुरक्षित होकर जर्जर है। 3400 स्कूलों में तो शौचालय ही नहीं है, 1895 स्कूल शिक्षक विहीन है, 10 हजार स्कूलों में बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो कैसे गढ़ा जाएगा नौनिहालों का सुरक्षित भविष्य ?

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.एल.जैन ने प्रदेश की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रतापसिंह, जनजातीय कार्यमंत्री कुं. विजय शाह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि देश की आजादी के 79 वर्षों के बाद भी प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन प्रदेश सरकार इन लक्ष्यों तक नही पहुंच पाई है। श्री जैन ने बताया कि भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट जो म.प्र. विधानसभा में प्रस्तुत की गई उसमे प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ने के साथ बुनियादी ढांचा भी ध्वस्थ नजर आया। प्रदेश में 2 लाख 89 हजार शिक्षकों के पद स्वीकृत है इसमे 1 लाख 15 हजार 678 पद रिक्त है। प्रदेश के 83 हजार 514 स्कूलों में से 5 हजार स्कूलों के भवन बच्चों के लिये सुरिक्षत नहीं होकर जर्जर है यही नहीं 3 हजार 400 स्कूलों में शौचालय भी नहीं है। 10 हजार स्कूल तो ऐसे है जहां बिजली की सुविधाएं भी नहीं है। 1895 स्कूल तो ऐसी है जहां 1 भी शिक्षक नहीं है। 40 हजार स्कूलों में सुरक्षा के लिये बाउंड्रीवाल भी नहीं है। हजारों स्कूलों में शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। अनेक स्कूल तो तबेले या झोपड़ियों में संचालित हो रही है।

डिजीटल इंडिया की बात करने वाले प्रदेश के 59 हजार स्कूलों में कम्प्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है अनगिनत समस्याओं के बीच चौकाने वाला आंकड़ा यह है कि पिछले 10 वर्षो में पहली से 12वीं तक में 22 लाख 3 हजार विद्यार्थियों की कमी शासकीय स्कूलों में दर्ज की गई है जबकि इन 10 वर्षो में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। श्री जैन ने कहा है कि ये आंकड़े दर्शाते है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त गिरावट आई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जनवरी 26 मे निर्देशित किया है कि देश के प्रत्येक स्कूल चाहे वह निजी हो शासकीय बच्चियों के लिये मुफ्त सेनेटरी पेड एवं छात्र-छात्राओं के लिये पृथक-पृथक टायलेट होना जरूरी है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। श्री जैन ने बड़वानी जिले की शैक्षणिक व्यवस्थाओं में कमी का उल्लेख करते हुये जिले की 2 हजार 547 स्कूलों में प्रथम श्रेणी प्राचार्य के शत्प्रतिशत पद एवं उ.मा.वि. के 90 प्रतिशत प्राचार्यो के पद के अलावा शिक्षकों की भारी कमी व बुनियादी सुविधाओं की ओर भी शासन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है। एक ओर तो प्रदेश सरकार बजट की 16 प्रतिशत राशि यानी 50 हजार लाख करोड़ की राशि मुफ्त की योजनाओं में खर्च कर व्यक्ति को श्रम से दूर कर रही है वहीं शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने के लिये खजाना खाली नजर आता है। कमीशनखोरी के कारण मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी होने के कारण करोड़ों रूपये की शासकीय निधि का दुरूपयोग हो रहा है दिखावे के लिये कुछ लोगों के खिलाफ निलबंन की कार्यवाही कर दी जाती है लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में भ्रष्टाचार की यह बेल निरंतर फल फूल रही है। श्री जैन ने प्रदेश के नौनिहालों के सुनहरे भविष्य के लिये एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के लिये उक्त समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फंसे हैं 20,000 भारतीय नाविक

- ईरान युद्ध के बीच भारत ने लॉन्च किया स्पेशल ऑपरेशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में बातचीत फेल होते ही भारत अलर्ट मोड में आ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे 18 जहाजों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन जहाजों पर लदा माल भारत आना है। भारत के इस ऑपरेशन का उद्देश्य एनर्जी सिक्योरिटी को बहाल करना और भारत के बंदरगाहों पर जमा माल साफ करना है। जंग फिर से शुरू होने की अटकलों के बीच भारत सरकार ने यह ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया, ताकी तेल टैंकर, एलपीजी और पीएनजी से लदे जहाज सुरक्षित रूप से लौट सकें। बता दें कि ईरान बनाम इजरायल और अमेरिका के युद्ध के कारण भारतीय बंदरगाहों पर गंभीर रुकावटें आ रही हैं।

एलपीजी जहाज ने पार किया होर्मुज

बंदरगाहों को इन जहाज़ों को बर्थिंग में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लिया है और मुंबई स्थित पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। भारत के अभियान से बंदरगाहों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जहां करीब 106,890 केजी के कंटेनर और बड़ी मात्रा में खराब होने वाला माल फंसा हुआ है।

असम के बाद अब बंगाल का रुख करेंगे हेमंत सोरेन

- टीएमसी के लिए मांगेंगे वोट, आदिवासी इलाकों पर फोकस

रांची (एजेंसी)। असम में अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही बंगाल का रुख करने जा रहे हैं। वहां वे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनावी अभियान को धार देंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि झामुमो के वरिष्ठ नेता पहले ही बंगाल पहुंचकर समन्वय की रूपरेखा तैयार करेंगे। ममता बनर्जी के समर्थन में झामुमो पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन ने तृणमूल के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका असर खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देखने को मिला था। इस बार भी मुख्य फोकस बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके होंगे। झारखंड से सटे जंगलमहल क्षेत्र के अलावा उत्तर बंगाल के जिलों में भी उनकी सभाएं प्रस्तावित हैं। इन इलाकों में झामुमो की विचारधारा और सामाजिक आधार को विस्तार देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

प्रेमी ने नहीं की बात तो टावर पर चढ़ी प्रेमिका

चार दिन से रुठा था लवर, टावर पर चढ़ देने लगी जोर-जोर से आवाज

टीकमगढ़ (नप्र)। टीकमगढ़ जिले के बैरवार गांव में रविवार को प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया। यहां एक युवती अपने प्रेमी से चार दिन से बात न होने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

सुबह करीब 5 बजे युवती के टावर पर चढ़ने और चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही जतारा पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। युवती करीब चार घंटे तक टावर पर चढ़ी रही और लगातार अपने प्रेमी का नाम लेकर बुला रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। प्रशासन के आश्वासन और प्रेमी के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस की समझाइश पर युवती टावर से नीचे उतरी।

दुश्मनों के लिए काल बनेगी ध्रुवास्त्र मिसाइल

एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी कल्पना, अब सेना में होगी शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा विकसित ध्रुवास्त्र मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का आधुनिक संस्करण है, जिसे पहले हेलिना के नाम से जाना जाता था। यह मिसाइल न केवल भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि युद्ध के मैदान में खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारतीय वायुसेना और थल सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी।

थर्ड-जनरेशन फायर एंड फॉरगेट प्रणाली शामिल

ध्रुवास्त्र भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसकी परिकल्पना 1980 के दशक में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई थी। नाग मिसाइल परिवार के तहत अब तक जमीन से दागी जाने वाली नाग, कैरियर और मैन-पोर्टेबल जैसे कई संस्करण तैयार किए जा चुके हैं। ध्रुवास्त्र इसी कड़ी का हवाई संस्करण है। ध्रुवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी थर्ड-जनरेशन फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है। एक बार लक्ष्य पर लॉक होने के बाद, मिसाइल ऑटोमैटिक रूप से उसे ट्रैक कर नष्ट कर देती है।

स्वदेशी हेलीकॉप्टरों की ताकत

ध्रुवास्त्र को विशेष रूप से लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित रुद्र और प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों से दागा जा सकता है। हाल ही में सरकार ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर दिए हैं। इन हेलीकॉप्टरों पर ध्रुवास्त्र की तैनाती से भारतीय सेना को सीमा पर दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त मिलेगी। सरकार ने सितंबर 2023 में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से 200 से अधिक ध्रुवास्त्र मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी थी। एक मिसाइल की लागत 1 करोड़ रुपये से भी कम रहने का अनुमान है। इसकी तैनाती के बाद भारत को रूस या यूरोप से कोंकुर्स और मिलान जैसी पुरानी मिसाइलें आयात करने की जरूरत कम हो जाएगी। ध्रुवास्त्र की सफलता के बाद डीआरडीओ मिशन में काम कर रहा है।

इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही

ईरान-अमेरिका के बीच नहीं बन पाई बात

अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले- हमने उन्हें फाइनल ऑफर दिया

ईरान बोला-ट्रम्प की शर्तें ज्यादा सख्त, उन्हें मानना असंभव

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। यह 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंसा है। वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थीं, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। वेंस ने यह भी कहा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखना है कि ईरान इसे मानता है या नहीं। वहीं, ईरान ने कहा कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं। इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया।

टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ दिए

- पीएम बोले-अब 15 साल का हिसाब देना होगा
- कहा-सिलीगुड़ी की जनसभा उनकी नींद उड़ा देगी

कोलकाता (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि चुनाव के बाद बंगाल से टीएमसी का जाना तय है। कल मेरे रोड शो में लोगों ने जो प्यार दिखाया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज सिलीगुड़ी की यह जनसभा टीएमसी की नींद उड़ा देगी। पीएम का रविवार को पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन था। वे सिलीगुड़ी में जनसभा कर रहे थे। मोदी ने दार्जिलिंग की सभी 5 और जलपाईगुड़ी जिले की सभी 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा- टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ दिए, लेकिन यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसे देती है। आपने टीएमसी के निर्मम शासन काल में इतने सालों में पश्चिम बंगाल की बर्बादी देखी है। उन्हें 15 साल का हिसाब देना होगा। सभा के दौरान पीएम ने सीएए (नागरिकता (संशोधन) अधिनियम) का भी जिक्र किया। उन्होंने 'कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ' के नारे लगाते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार निर्मम है, लेकिन हमने मदद की है।

देश में एक 'टुकड़े-टुकड़े गिरोह' सक्रिय है

देश में एक टुकड़े-टुकड़े गिरोह सक्रिय है, जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की धमकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी की जनसभा में कहा कि टीएमसी ने काम नहीं केवल काले कारनामे किए हैं। उन्होंने ने नॉर्थ बंगाल की संरचना को पीछे रखा हुआ है। सिलीगुड़ी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पाई-पाई का हिसाब मांग रही है।

महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार की पूरी तैयारी

बीजेपी ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन की व्हिप

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उनसे गुरुवार से शुरू होने वाले संसद के विस्तारित बजट सत्र के दौरान अपने-अपने सदन में उपस्थित रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने एवं इन्हें पारित करने के लिए पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत बुधवार (आठ अप्रैल) को उन प्रारूप विधेयकों को मंजूरी दे दी जिनका उद्देश्य 2029 के संसदीय चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना है। इनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को भेजे संदेश में कहा, 16 से 18 अप्रैल 2026 तक यानी आगामी गुरुवार से शनिवार तक लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों को तीन-लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है। इसने कहा, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त तीनों तिथियों पर सदन में उपस्थित रहें। संदेश में कहा गया, सदन में उपस्थिति अनिवार्य है। कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और सदन में अपनी निर्बाध उपस्थिति सुनिश्चित करें।

परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग बिल लाएगी सरकार

राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संशोधन बिल के एक संविधान साथ-साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी। ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने सभी दलों को चिट्ठी लिखी

पीएम मोदी ने लिखा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की इच्छा सभी पार्टियों ने लंबे समय से जताई है, अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के जवाब में पत्र लिखकर कहा कि राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। खड़गे ने यह भी मांग की कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जाए। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

हेडगेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस बनाया था

- भागवत बोले-हिंदू समाज में एकता की कमी, ये बार-बार गुलामी की बड़ी वजह

निजामाबाद (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को विदेशी शासन से आजाद कराने और हिंदुओं के बीच फूट को खत्म करने के मकसद से आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का मानना था कि समाज में एकता की कमी ही बार-बार गुलामी की बड़ी वजह रही। संघ प्रमुख ने कहा कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए राजनीतिक और हथियारबंद विरोध समेत कई रास्तों पर काम किया था। भागवत ने कहा कि आजादी के लिए काम करते हुए हेडगेवार को यह एहसास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाने वाले पहले बाहरी शासक नहीं थे। उनके मुताबिक, समस्या सिर्फ बाहर से आने वाली ताकत नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर भी एक कमी थी। भागवत शनिवार को तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कंडाकुर्थी गांव में श्री केशव स्फूर्ति मंदिर के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। यह गांव हेडगेवार का पैतृक गांव है। उन्होंने कहा- हममें कोई कमी थी, जिसकी वजह से हमें बार-बार हार का सामना करना पड़ा। इसलिए उस कमी को दूर करना जरूरी था। हिंदुत्व का मतलब दूसरों के साथ मिलकर रहना है।

परिक्रमा

खेती-किसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती मोहन सरकार

अरुण पटेल

लेखक सुबह सबेरे के प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार खेती-किसानी और किसानों को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपनी योजनाओं को लागू करने के प्रति पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रही है और उसका प्रयास है चूंकि मध्यप्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए यहां पर किसानों को साथ जोड़कर और उनका दिल जीतकर विकास की नई गंगा बहाई जा सकती है। जहां तक किसानों का सवाल है किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी माने जा सकते हैं। खेती-किसानी यदि संपन्न होगी तो किसानों की न केवल दशा सुधरेगी बल्कि उन्हें अपने आपको संवारने के साथ ग्रामीण विकास को भी नये पंख लगेंगे जिससे आगे चलकर मध्यप्रदेश पूरी तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ता जायेगा। मोहन यादव सरकार की यह सोच कि किसानों की जिन्दगी में यदि बदलाव आयेगा तो उससे गांवों तक विकास की नई राह और तेज होने में समय नहीं लगेगा। किसान समाज का वह वर्ग है जो हर घर को प्रभावित करता है, खेती-किसानी यदि मजबूत होगी तो प्रदेश को विकास का एक आधारभूत ढांचा मिल जायेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह सोच भी अपने आपमें काफी मायने रखती है कि देश की सीमा पर जवान और खेती में किसान दोनों का समान महत्व है और दोनों ही अपनी मिट्टी के लिए प्राणपण से सेवा में लगे रहते हैं। यह बात सही है कि हमारे किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यही अपनी हमारी असली ताकत है क्योंकि इसके बिना हमारे भोजन की थाली अधूरी रहेगी। वास्तव में खेती-किसानी आसान काम नहीं है बल्कि यह बड़े जोखिम का काम है क्योंकि हमारे किसान पूरी मेहनत व लगन से देशवासियों के पेट का पोषण करते हैं। जब किसान को पूरे तरीके से सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी और वह सम्पन्न होगा तब ही यह कहा जा सकेगा कि किसान प्रदेश के विकास में अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन कर रहा है। किसानों की मेहनत से ही हमारे देश और प्रदेश का खाद्यान्न निर्यात दोगुना पहुंच गया है, चूंकि उसकी उपज से ही सबका पेट भरता है इसलिए उसके विकास के प्रति राज्य सरकार भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केन्द्र की सरकार भी। सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों का ही समान महत्व है क्योंकि एक देश की सीमा की रक्षा करता है और घुसपैठ रोकता है तो दूसरा खेतों में कड़ी मेहनत कर अनाज का उत्पादन करता है।

किसानों और सेना का कल्याण ही भाजपा सरकार का एकमेव लक्ष्य है और इसके लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के रुप में हर पात्र किसान के बैंक खाते में भी सीधे 6000 रुपये भेजे जा रहे हैं जिससे कि वे खाद, बीज और किसानी के अन्य जरुरी सामान खरीद सकें, यह किसानों की मेहनत का सम्मान है। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपयों की सहायता किसान भाईयों को दे चुकी है।

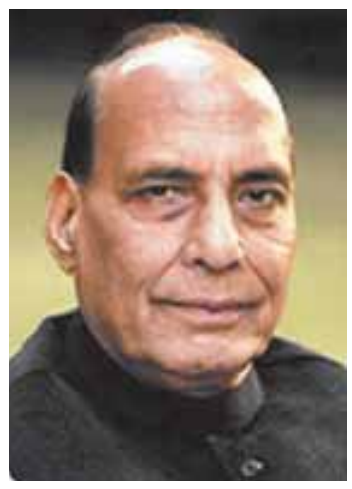

किसानों के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए राजनाथ यह भी कहते हैं कि गांव, गरीब, नारी, युवा और खेती-किसानी की लगातार बेहतरी के लिए हमारी भाजपा सरकार के प्रयास हमेशा जारी रहेंगे। रायसेन के दशहरा मैदान में जो बात राजनाथ ने कही है वह भी सही प्रतीत होती क्योंकि किसानों को सीधे नकद पैसा मिल रहा है।

किसानों का विकास और भाजपा की सोच

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि इस समय किसानों के विकास का महायज्ञ चल रहा है। राजनाथ सिंह पहले भी केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं और वे स्वयं एक किसान पुत्र हैं इसलिए किसानों के दुख दर्द को वे भली-भांति समझते हैं। इस प्रकार रायसेन की पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और कृषि का जो संगम हो रहा है वह एक प्रकार से महायज्ञ है और किसान के लिए एक पाठशाला की तरह है। वास्तव में इसे किसानों की एक पाठशाला ही कहा जायेगा क्योंकि जब किसानों को कृषि की नवीन तकनीक देखने-समझने का अवसर मिलेगा तो उनका भविष्य भी संवरेगा। रायसेन जिला कृषि सहित हर क्षेत्र में आगे चल रहा है क्योंकि यहां का धान और गेहूं दुनिया भर में प्रसिद्ध है तो वहीं इससे मध्यप्रदेश के किसानों और खेतिहर मजदूरों की शान बढ़ती है। चूंकि यह महायज्ञ रायसेन में हो रहा है और रायसेन की अपनी प्रदेश के साथ ही वैश्विक पटल पर ख्याति है, रायसेन में ही दो विश्व धरोहरें सांची स्तूप और भीमबेठका हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक शक्तिशाली विकसित भारत बनना है और देश को मजबूत इरादों वाले प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री मिले हैं।

और यह भी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश के लिए राजनाथ सिंह को शुभंकर मानते हैं, क्योंकि वे मध्यप्रदेश में खेती-किसानी को नई दिशा देने आये हैं। इस प्रकार राज्य में खेती-किसानी को एक मजबूत आधार मिल रहा है।

पुलिस का एक्शन, 450 बदमाश चेक, 350 पर कार्रवाई, 218 शराबी पकड़े

सरप्राइज चेकिंग में गुंडे-बदमाशों पर शिकंजा, अवैध हथियार पकड़ाए

इंदौर। शहर में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर 11-12 अप्रैल की रात शहरभर में सरप्राइज चेकिंग और पेट्रोलिंग की गई, जिसमें करीब 450 गुंडे-बदमाशों की जांच कर 350 के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 141 वारंट तामील किए, जिनमें स्थायी, गिरफ्तारी और जमानती वारंट शामिल हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 218 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। चेकिंग के दौरान अवैध शराब बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया,जबकि चाकू लेकर घूम रहे 3 बदमाशों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इसके अलावा 84 असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन पेट्रोलिंग के साथ पैदल गश्त कर निगरानी बढ़ाई। कई फरार अपराधी भी इस दौरान पकड़ में आए।

दो आरोपी 6 माह निरुद्ध – नगरीय ज़ोन-02 क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की खरीदी / बिक्री करने वाले आरोपियों की धरपकड़ तथा अवैध मादक पदार्थ बिक्री में संलिप्त आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी खजराना द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अपराधों में लिप्त बदमाश सैयद रेहान उर्फ मांडा के विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्यवाही करते हुये इसके विरूद्ध प्रकरण तैयार किया गया। न्यायालय संभाग आयुक्त द्वारा आरोपी सैयद रहमान को छः माह की अवधि के लिए भोपाल जेल में निरुद्ध रखने के आदेश दिए गए। इसी प्रकार थाना प्रभारी रावजी बाजार एवं टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्कर सचिन आर्य के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के तहत वैधानिक प्रभावी कार्यवाही की गई। सचिन के विरुद्ध भी आदेश पारित कर आरोपी को 6 माह के लिए सेंट्रल जेल भोपाल में निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया।

होमगार्ड जवान से अभद्रता, कार से बेरीकेड्स तोड़े, झूमाझटकी

- शासकीय कार्य में बाधा डालने और तोड़फोड़ का केस

इंदौर। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ चेकिंग पाइंट पर रखे बैरिकेड्स तोड़े, बल्कि ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड जवान के साथ झूमाझटकी भी की। पुलिस के मुताबिक, होमगार्ड सैनिक अनिल अटारे को सुपर कॉरिडोर इलाके में रांग साइड से आने वाले वाहनों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान स्विफ्ट डिजायर कार में सवार युवक वहां पहुंचा और बंद मार्ग होने के बावजूद जबरन घुसने की कोशिश करने लगा। मना करने पर आरोपी ने बैरिकेड्स को लात मारकर गिरा दिया और खुद को अरुण गोस्वामी बताते हुए विवाद करने लगा।

धमकी देकर बात की

आरोप है कि युवक ने होमगार्ड जवान अनिल अटारे की वर्दी पकड़कर खींची, जिससे उनके बटन टूट गए और चश्मा भी गिर गया। मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों के सामने भी आरोपी ने धमकी भरे अंदाज में बात की और पुलिस को हल्के में लेने की कोशिश की। घटना के बाद अनिल ने अपने साथी के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अरुण गोस्वामी और उसके साथियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वंदे भारत 16 नए कोच के साथ रवाना

इंदौर। इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन के लिए हाल ही में आए 16 डिब्बों का नए रैक के साथ शनिवार को रवाना हुई। जानकारी के अनुसार यह 16 नए रैक (नारंगी रंग) शुक्रवार की रात को ही इंदौर आए थे। रेलवे के इस निर्णय का फायदा यात्रियों को हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन सुबह छह बजकर 10 मिनट पर इंदौर से चलकर दोपहर दो बजकर 35 पर नागपुर पहुंचती है। इसी प्रकार नागपुर से दोपहर तीन बजकर 20 मिनट पर चलकर रात 11 बजकर 50 बजे इंदौर पहुंचती है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार नए 16 कोच शुक्रवार को इंदौर आए थे। इन्हीं नए कोच के साथ शनिवार को इंदौर-वंदे भारत रवाना हुई। त्योहारों के दौरान इंदौर से नागपुर तक भारी भीड़ रहती है। यात्रियों का मानना है कि 16 कोच लगने से सीटों की भारी कमी दूर हो चुकी है। पहले इस रूट पर मात्र आठ डिब्बों वाली वंदे भारत ही चल रही थी। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे 16 कोच के साथ चला रहा है।

प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में मदर मिल्क बैंक शुरू होगा

इंदौर के मदर मिल्क बैंक ने बचाई एक हजार से अधिक की जान

प्रदेशभर में शुरू होगा मिल्क बैंक

डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए एमटीएच रोल मॉडल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अधीन सरकारी अस्पतालों में भी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रीमैच्योर या एसएनसीयू में भर्ती गंभीर नवजातों को इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर इन्हें समय पर मां का दूध मिल जाए तो उनकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार बच्चा अनाथ होता है, मां की मौत हो जाती है या किसी कारणवश दूध नहीं बनता। ऐसे में मां का दूध मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मिल्क बैंक की मदद से दूसरी मां के पोषक दूध से नवजात को नया जीवन मिलता है।

इंदौर। एमजीएम मेडिकल कालेज के अंतर्गत संचालित एमटीएच अस्पताल में प्रदेश के पहले मदर मिल्क बैंक का संचालन हो रहा है। यह मदर मिल्क बैंक देश में रोल मॉडल बन चुका है। प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में अब मिल्क बैंक खोलने की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2023 में शुरू हुए सेंटर से अब तक एक हजार से अधिक नवजातों की जान बचाई गई है। सेंटर में काउंसलिंग के बाद महिलाओं ने 210 लीटर दूध डोनेट किया है। प्रबंधन के मुताबिक 2023 से मिल्क बैंक शुरू होने के बाद नवजात मृत्यु दर 25 प्रतिशत से घटकर 11 तक आ गई है। कई बार तो यह 10 प्रतिशत से कम भी रही है। अब डिस्चार्ज रेट भी 85 प्रतिशत हो गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि मां का दूध बच्चों के लिए जरूरी है। अगर किन्हीं कारणों के चलते नवजात को मां का दूध नहीं मिले और वह कमजोर, बीमार, अनाथ प्री-टर्म हो तो उसकी मौत हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिल्क बैंक की शुरुआत हुई। इससे माध्यम से प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चों को जन्म से ही अन्य मां का पौष्टिक दूध मिला है। बता दें कि एमटीएच अस्पताल में प्रसूताओं के लिए करीब 150 बेड की व्यवस्था है। साथ ही यहां एसएनसीयू की क्षमता लगभग 60 बेड की है।

रिंग रोड से होकर रेडिसन चौराहे आने वाली स्लीपर बसें प्रतिबंधित

- पिपलियाहाना से रिंग रोड और रेडिसन पर आवागमन नहीं

इंदौर। रिंग रोड पर बढ़ते हुए यातायात दबाव को देखते हुए स्लीपर बसों का रिंग रोड से डायवर्सन कर परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक बसों का पिपलियाहाना से रिंग रोड रेडिसन आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

व्हाइट चर्च की ओर से पिपल्याहाना होकर चलने वाली स्लीपर बसें स्कीम नं. 140, अग्रवाल स्कूल चौराहा, बिचौली अंडर ब्रिज होकर, बाईपास से बेस्ट प्राइस तक एवं बेस्ट प्राइस से स्टार चौराहा तक आने की अनुमति रहेगी।

स्टार चौराहा से वापस बेस्ट प्राइस होते हुए बाईपास की ओर मार्ग रहेगा। बस चालक उक्त मार्ग का उपयोग कर संचालन करें। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

परिवर्तित मार्ग यह होगा

- पिपलियाहाना से रेडिसन रोड पर स्लीपर/इंटर स्टेट बसों का आवागमन नहीं होगा।
- व्हाइट चर्च की ओर से पिपल्याहाना होकर चलने वाली स्लीपर/इंटर स्टेट बस का स्कीम नं. 140, अग्रवाल स्कूल चौराहा, बिचौली अंडर ब्रिज होकर हाईवे पर आ-जा सकेगी। अर्थात् यह बसें रिंग रोड होकर रेडिसन की ओर नहीं जा सकेंगी।
- बसें बायपास से स्टार चौराहे तक आ सकेंगी। लेकिन रेडिसन तरफ आना प्रतिबंधित रहेगा।
- इंटर स्टेट बस मूसाखेड़ी चौराहा व तीन इमली से पालदा रोड होते हुए हाईवे पर जा सकेंगी।

ट्रैफिक जवानों को ड्रोन प्रशिक्षण, मुख्य मार्ग चौराहों पर निगरानी

नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई

इंदौर। शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर पिक आवर्स के दौरान प्रभावी निगरानी की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ड्रोन से प्राप्त इनपुट के आधार पर मौके पर तैनात यातायात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

ड्रोन सर्विलांस के दायरे को और अधिक विस्तारित करने के लिए यातायात के चारों जोनों में अलग-अलग ड्रोन सर्विस टीमों का गठन किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस के प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा यातायात पुलिस को ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे तकनीकी रूप से दक्ष होकर फील्ड में बेहतर कार्य कर सकें। पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चारों जोनों में अलग-अलग टीमों द्वारा पिक आवर्स के दौरान ड्रोन के माध्यम से यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। राजवाड़ा एवं विजयनगर क्षेत्रों में ड्रोन में लगें पीए सिस्टम द्वारा अनाउंसमेंट भी किए गए, जिससे आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके।

इन स्थानों पर ड्रोन से निगरानी

- जोन-1 के नरेंद्र तिवारी मार्ग, रंजीत हनुमान मार्ग गोपुर चौराहा क्षेत्र।
- जोन-2 के विजयनगर चौराहा, रसोमा, भमोरी, सयाजी, रेडिसन, सत्य साई क्षेत्र।
- जोन-3 के गांधी चौक, व्हाइट चर्च आरएनटी मार्ग, मधुमिलन, दावा बाजार क्षेत्र।
- जोन-4 के राजवाड़ा, यशवंत रोड, जवाहर मार्ग, खजूरी बाजार, सराफा क्षेत्र।

संपादकीय

मप्र: बैंकों का डूबता पैसा

हर महीने कर्ज पर कर्ज लेती जा रही मध्यप्रदेश सरकार के लिए चेतावनी की घंटी है कि राज्य में सरकारी योजनाओं का ज्यादातर पैसा डूबत खाते में जा रहा है। ये पैसा ज्यादा सरकारी गारंटी का है, जो विभिन्न बैंकों ने हितग्राहियों को दिया और जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई। यानी सरकारी गारंटी में बैंकों के अब तक 2100 करोड़ रू. डूब चुके हैं, जो कि एक बड़ी रकम है। मीडिया में छपी सरकार और बैंकों की 25 मार्च को जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहीं स्वरोजगार और आवास योजनाओं की सेहत बिगड़ती जा रही है। जिन योजनाओं को युवाओं और गरीबों का सहारा बनना था, वे बैंकों का सिरदर्द बन गई हैं। सीएम ग्रामीण आवास मिशन में तो बकाया राशि का 67.9% हिस्सा एनपीए (डूबत कर्ज) हो चुका है, जो कि 1,670 करोड़ रुपए है। कुछ ऐसा ही हाल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और सीएम स्वरोजगार योजना का भी है। यहां लक्ष्यों की प्राप्ति तो 127% दिख रही है, लेकिन वसूली के मामले में बैंक हांफने लगे हैं। इन योजनाओं में 422 करोड़ (42.9%) एनपीए की श्रेणी में जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में पांच साल में एनपीए 21% तक बढ़ गया है। कुल मिलाकर ग्रामीण आवास व स्वरोजगार योजनाओं में ही करीब 2100 करोड़ एनपीए में हैं। चार साल में एनपीए बढ़ने का ये ट्रेंड मार्च 2022- 46.3% मार्च 2023 - 49.9% मार्च 2024 - 53.3% मार्च 2025 - 63.1% दिसंबर 2025 - 67.9% (यह खतरनाक स्थिति का संकेत है) ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत विगत 5 साल में 46% से 68% पर पहुंचा एनपीए सीएम ग्रामीण आवास में एनपीए 5 साल में 46 से 68% तक हो गया है। बैंकों के मुताबिक सरकार से हुए एक एमओयू की वजह से इन खातों को बंद करने वन टाइम सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू स्वरोजगार में सिर्फ 11.8% उपलब्धि इस वर्ग के लिए बनी योजनाओं में उपलब्धि मात्र 11.8% रही है। यानी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ अब भी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें एक से 10 लाख तक लोन मिलता है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में तो आधे आवेदन पेंडिंग इस स्कीम में पांच हजार के लक्ष्य के मुकाबले 2 हजार 743 आवेदन मंजूर हुए हैं। यह 54.8% है। इसमें अजजा को 10 हजार से एक लाख तक कर्ज 7% ब्याज अनुदान पर मिलता है। जन-धन खाते 'धन' से भरे मप्र में मार्च 2026 तक 4.66 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। वर्ष 2015 में यह संख्या मात्र 1.19 करोड़ थी। इनमें रू. 18,318 करोड़ रुपए जमा हैं। यानी हर खाते में औसत बैलेंस रू. 3,931 है, जो 2015 के रू. 445 के मुकाबले काफी ज्यादा है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 61% खाते हैं। इसमें भी महिलाएं 55% के साथ पुरुषों से आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या आधी हो गई है। दस साल पहले 86 लाख थे, अब 43 लाख हैं। सर्वाधिक 17.8 लाख खाते सागर में हैं, जहां रू. 680.9 करोड़ जमा। सिंगरौली (1.73 लाख), डिंडोरी (1.56 लाख) और बुरहानपुर (1.53 लाख) जैसे जिलों में भी खातों की संख्या में प्रगति दर्ज की गई है। रिपोर्ट का सकारात्मक संकेत यह है कि प्रदेश में पुरुषों और कंपनियों के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं कर्ज चुकाने में सबसे ईमानदार हैं। इन्हें 3,570 करोड़ रू. के वितरण के बाद भी महिला स्व सहायता समूहों का एनपीए मात्र 2.4% है। सरकारी योजनाओं का सारा बोझ केवल सरकारी बैंकों पर है। जहां सरकारी बैंक लक्ष्यों से 300% ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि निजी बैंक इसके प्रति बेपरवाह हैं।

बारूद बनाम भोजन: क्या युद्ध भूख को जन्म देगा?

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

विश्व इतिहास में युद्ध केवल सीमाओं को नहीं बदलते, वे मनुष्यता के सबसे बुनियादी प्रश्न भोजन को भी झकझोर देते हैं। जब भी मध्य-पूर्व की धरती पर बारूद की गंध फैलती है, तब दुनिया के कोनों में बैठे करोड़ों लोग अनायास ही यह सोचने लगते हैं कि कहीं यह संघर्ष उनकी थाली तक तो नहीं पहुँच जाएगा। हालिया खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की आशंकाओं ने भी वैश्विक खाद्य संकट की चर्चा को हवा दी है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में यह भय निकट भविष्य की वास्तविकता है, या फिर यह आशंका अधिकतर मनोवैज्ञानिक है? दरअसल, खाड़ी क्षेत्र का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनोखा स्थान है। यहाँ की धरती तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, और यही ऊर्जा स्रोत दुनिया के औद्योगिक ढांचे को गति देते हैं। एक पुरानी कहावत है कि 'मध्य-पूर्व हाइड्रोकार्बन बेचकर कार्बोहाइड्रेट खरीदता है।' इसका आशय यह है कि ये देश ऊर्जा निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। परंतु इस समीकरण का एक दूसरा पहलू भी है, उर्वरकों का उत्पादन। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, जिनके बिना आधुनिक कृषि की कल्पना अधूरी है, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस से बनते हैं, और खाड़ी क्षेत्र इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

यहीं से चिंता की पहली लहर उठती है। यदि इस क्षेत्र में युद्ध होता है, विशेषकर ईरान और उसके आसपास के समुद्री मार्गों जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान आता है, तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि सीधे उर्वरकों के उत्पादन को प्रभावित करती है, क्योंकि गैस उनके निर्माण का मुख्य कच्चा माल है। यदि उर्वरक महंगे या दुर्लभ हो जाते हैं, तो किसानों के लिए उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे भविष्य की फसलों पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह पूरा परिदृश्य जितना भयावह प्रतीत होता है, उतना तत्कालिक नहीं है। वर्तमान में वैश्विक खाद्य बाजार अपेक्षाकृत स्थिर है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि दुनिया के पास अभी पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद हैं। गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के स्टॉक पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। यह भंडारण किसी संकट के समय एक ढाल का कार्य करता है, जिससे अचानक आपूर्ति में कमी होने पर भी बाजार पूरी तरह चरमराता नहीं।

यदि हम हाल के इतिहास की ओर देखें, तो रूस-यूक्रेन युद्ध इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। उस समय दुनिया को वास्तव में खाद्य संकट की आशंका का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रूस और यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं और अन्य अनाजों का

बड़ा हिस्सा निर्यात करते थे। युद्ध ने न केवल उत्पादन को प्रभावित किया, बल्कि बंदरगाहों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप, कीमतों में भारी उछाल आया और कई देशों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा

परंतु वर्तमान खाड़ी संकट उस स्थिति से भिन्न है। यहाँ युद्ध यदि होता भी है, तो उसका प्रभाव अधिकतर ऊर्जा बाजार तक सीमित रहने की संभावना है, न कि सीधे कृषि उत्पादन केंद्रों पर। खेतों में खड़े फसलें बमबारी की चपेट में नहीं हैं, और न ही अनाज के विशाल भंडार युद्धभूमि में तब्दील हो रहे हैं। इसीलिए खाद्य संकट की आशंका फिलहाल दूर की कौड़ी प्रतीत होती है।

फिर भी, उर्वरकों का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, ये तीनों कृषि के आधार स्तंभ हैं। इनमें से नाइट्रोजन का उत्पादन सबसे अधिक ऊर्जा-निर्भर है। यदि गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो उर्वरकों की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है जब उर्वरकों के दाम अचानक कई गुना बढ़ गए थे, जिससे किसानों को अपनी लागत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कृषि एक धीमी प्रक्रिया है; इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। यदि आज उर्वरकों की कमी होती है, तो उसका असर अगली फसल में दिखेगा, वह भी धीरे-धीरे। इसके अलावा, किसान पूरी तरह उर्वरकों का उपयोग बंद नहीं कर देते, बल्कि उनकी मात्रा कम कर देते हैं। इससे उत्पादन में गिरावट आती है, परंतु यह गिरावट अचानक और विनाशकारी नहीं होती।

इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक कृषि केवल नाइट्रोजन पर निर्भर नहीं है। फॉस्फेट और पोटाश भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और इनकी आपूर्ति विभिन्न देशों में फैली हुई है। हालांकि, रूस और बेलारूस जैसे देश पोटाश के बड़े निर्यातक हैं, और किसी भी वैश्विक तनाव का असर इनके निर्यात पर पड़ सकता है, जिससे कीमतों में उछाल आता है। इसके बावजूद, एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एशिया और विशेषकर भारत तथा चीन जैसे देशों में उर्वरकों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का सीधा बोझ किसानों पर नहीं पड़ता, बल्कि सरकारें उसे वहन करती हैं। इस व्यवस्था के कारण खाद्य उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर बना रहता है, और आम जनता को महंगाई का झटका कम लगता है।

खाद्य संकट के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू है- भंडारण और वितरण प्रणाली। आज की दुनिया 2007-08 के खाद्य संकट की तुलना में कहीं अधिक तैयार है। उस समय वैश्विक भंडार न्यूनतम स्तर पर थे, और अचानक आई कीमतों की लहर ने कई देशों में दंगे तक भड़का दिए थे। आज स्थिति भिन्न है। देशों ने अपने भंडारण को मजबूत किया है, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाया है। फिर भी, खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष लंबा खिंचता है और ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो इसका असर धीरे-धीरे कृषि पर पड़ेगा। उत्पादन लागत बढ़ेगी, परिवहन महंगा होगा, और अंततः उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया धीमी होगी, परंतु स्थायी हो सकती है।

इस पूरे परिदृश्य में एक गहरी मानवीय सच्चाई भी छिपी है। भोजन केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब भी युद्ध होता है, सबसे पहले और सबसे अधिक असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। विकसित देशों के पास भंडार और संसाधन होते हैं, परंतु विकासशील देशों में हर छोटी कीमत वृद्धि भी लाखों लोगों की थाली से रोटी छीन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल वर्तमान की स्थिति को देखकर संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के प्रति भी सजग रहें। सरकारों को चाहिए कि वे अपने खाद्य भंडार को मजबूत रखें, उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करें। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा है, न कि किसी एक देश का।

खाड़ी युद्ध और वैश्विक खाद्य संकट के बीच संबंध एक जटिल और बहुआयामी विषय है। यह संबंध सीधा और तात्कालिक नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और दीर्घकालिक है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना उचित होगा कि दुनिया अभी किसी बड़े खाद्य संकट के कगार पर नहीं खड़ी है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि यदि हम सतर्क नहीं रहे, तो यह स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। युद्ध की आहट भले ही दूर कहीं गूंज रही हो, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि हमारी थालियों तक पहुँच सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम भय और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखें, और भविष्य की चुनौतियों के लिए आज ही तैयार हो जाएं। यही विवेक, यही दूरदर्शिता, हमें संभावित संकट से बचा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए।

असम, केरल और पुडुचेरी में बंपर मतदान के मायने

राजनीति

प्रमोद भार्गव
लेखक पत्रकार हैं।

देश के दो राज्य केरलम्, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बंपर मतदान ने न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि पूर्वानुमान लगाने वाले टीवी चैनलों को भी संशय में डाल दिया है। हालांकि जिस तरह का माहौल है, उससे तय है कि असम में भाजपा को एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा तारणहार बनने जा रहा है, वहीं केरल में सत्तारूढ़ दल सीपीआई के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन सकते में है। केरलम् में हुई 78.01 प्रतिशत मतदान ने सभी को चौंका दिया है। असम में जहां 85.38 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं पुडुचेरी में 89.81 मतदान हुआ है। 2021 की तुलना में केरलम् में 4.11, असम में 2.89 और पुडुचेरी में 11.91 प्रतिशत मतदान बढ़ा है। इस कारण केरल में संकेत मिलने लगे है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विरुद्ध एंटी इनकंबेंसी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। विजयन पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस संकेत से कांग्रेस नीत यूडीएफ प्रसन्न है। इस बार सीपीआईएम के खिलाफ मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर मतदान के लिए बाहर आया है। साफ है, इन राज्य-विधानसभाओं में मतदान के बढ़े प्रतिशत ने सारे मापदण्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

इन तीनों राज्यों में कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इन राज्यों में 5.31 करोड़ मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर चुनावी यज्ञ में अपनी आहुती देकर 1849 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया। असम में 2.50 करोड़ मतदाता और 722 उम्मीदवार हैं। यहां अभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा संभाले हुए हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है। सरमा ने जिस तरह से घुसपैठियों के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, उनसे एक बार फिर सरमा की वापसी तय लग रही है। क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या घुसपैठियों ने सीमावर्ती जिलों में न केवल स्थानीय मूल

निवासियों के संसाधनों को कब्जा लिया है, बल्कि असम का जनसांख्यकीय घनत्व बिगाड़ा हुआ है। धर्मांतरण के साथ ये घुसपैठिए देश-विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए है। स्थानीय जनजातीय समुदायों से इनका सांप्रदायिक संघर्ष भी निरंतर सामने आता रहा है। अतएव असम में घुसपैठिए बड़ा मुद्दा बनकर भाजपा को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। यदि सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो असम में घुसपैठियों की समस्या लगभग समाप्त हो जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित षाह भी घुसपैठ को अपनी सभाओं में बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करते रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति इस राज्य में इसलिए खराब होती रही है, क्योंकि वह असम के सीमावर्ती जिलों और बराक घाटी समेत पूरे असम में अवैध प्रवासियों को शरण देने की पैरवी करती रही है। इसलिए कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध किया और एसआईआर का भी विरोध किया। क्योंकि अपने मतदाता बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने घुसपैठियों को राशन, आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र बनवाने का काम किया हुआ है। असम में एसआईआर के बाद 2 लाख 43 हजार मतदाता कम हुए हैं। जबकि अभी भी ये घुसपैठिए बड़ी संख्या में मतदाता बने हुए हैं। केरल में पिनाराई विजयन को एंटी इनकंबेंसी के साथ क्षेत्रीय नेताओं की कमी का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल विजयन ने सेकंड लाइन के नेतृत्व को पनपने ही नहीं दिया है। इस कारण कई प्रभावशाली नेता अपने भविष्य की चिंता करते हुए वैचारिकता की परवाह किए बिना भाजपा और कांग्रेस की शरण में चले गए। ऐसे में इन नेताओं ने पार्टी कैडर की भी चिंता नहीं की। सबरीमाला मंदिर के धार्मिक विवाद ने भी विजयन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस मंदिर में गहनों की चोरी का मुद्दा भी विजयन के खिलाफ गया है। चूंकि सबरीमाला मंदिर का विवाद महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए केरल में महिलाओं ने मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। यहां महिला मतदाताओं की संख्या 1.39 करोड़ हैं, जो पुरुश मतदाताओं की तुलना में करीब 7 लाख अधिक है।

बावजूद मत प्रतिशत का सबसे अहम, सुखद व सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर रहा है। हालांकि फिलहाल हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मेरी सोच के मुताबिक ज्यादा मतदान की जो बड़ी खूबी है, वह है कि अब अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को वोट बैंक की लाचारगी से छुटकारा मिल रहा है। इससे कालांतर में राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब मतदान प्रतिषत 75 से 85 होने लगता हैं, तो किसी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहमियत कम हो जाती है। नतीजतन उनका संख्याबल जीत या हार की गारंटी नहीं रह जाता। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नगण्य हो जाती है। कालांतर में यह स्थिति मतदाता को धन व शराब के लालच से भी मुक्त कर देगी। क्योंकि कोई प्रत्याशी छोटे मतदाता समूहों को तो लालच का चुग्गा डालकर बरगला सकता है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से बड़े समूहों को लुभाना मुश्किल होगा ? बावजूद इन चुनावों में जातीय और अल्पसंख्यक राजनीति सभी दलों की कार्यशैली में खुले रूप में दिखाई दी है। साफ है, जातीय कुचक्र का धरातल नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से करने के उपाय किए जा रहे हैं।

बातें और बतंगड़

निर्मल आनंद
रमेश रंजन त्रिपाठी
लेखक स्तंभकार हैं।

पुरा मोहल्ला मानता है कि पकड़ हो तो सुमेरा जैसी, वरना न हो। डाकू भी किसी की ऐसी पकड़ न करते होंगे जैसी पकड़ सुमेरा की भाषा पर है। मजाल है कि एक शब्द इधर से उधर हो जाए ! कागज कलम से ज्यादा वे बोलने में उस्ताद हैं। गुजरा हुआ समय, कमान से छूटा तीर और जुबान से निकली बात कभी लौटाई नहीं जा सकती लेकिन सुमेरा को अपने शब्द वापस लेने का भी कमाल हासिल है। वैसे तो सुमेरा भाषा को मजबूती से पकड़कर रखते हैं लेकिन जिह्वा कभी फिसल भी जाए तो बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं करते। जैसे ही बात का बतंगड़ बना, पूरा मोर्चा दूसरे संभाल लेते हैं और सुमेरा मुस्कुराते हुए अपने फेंके कंकड़ से चुल्लू भर पानी में उठे तूफान के शांत हो जाने के यकीन के साथ दूसरे मुद्दे पर जुट जाते हैं।

सुमेरा सभी भाषाओं की बहुत इज्जत करते हैं। टपोरियों से लेकर अभिजात्य तक, सभी तरह की बोलियों को बिना संकोच अपनी वाणी से धन्य किया करते हैं। अक्सर उनके द्वारा बोले गए वाक्य में सभी तरह की भाषाएं ससम्मान जगह पा जाती हैं। सो, मुन्नाभाई मुरली प्रसाद शर्मा हों या डॉ. जे. सी. अस्थाना, सभी उनसे खुश रहते हैं। इनमें से किसी के साथ ट्वेल्थ फेल का चक्कर नहीं है। (श्री विधु विनोद चोपड़ा और श्री योगेश ईश्वर का आभार)। सुमेरा का बड़प्पन देखिए, उन्होंने अपनी पकड़ से मुक्त करने के लिए भाषा के रिश्तेदारों से कभी कोई फिरौती नहीं माँगी। डिक्शनरी में गिरावट या अत्याचार जैसे शब्द पाए जाते हैं लेकिन वे भाषा के संदर्भ में नहीं होते। वैसे भी शब्दकोश साक्षी मात्र होता है, बिना अपनी राय रखे शब्दों का अर्थ, इतिहास या तकनीकी जानकारी देता है। इसीलिए डिक्शनरी में रूखापन होता है, उसे एक बैठक में पढ़ जानेवाले नहीं मिलते। यह बात अलग है कि शब्दकोश के बिना किसी का काम भी नहीं चलता।

मानव मनोविज्ञान की मानद उपाधि वाले उस्ताद द्विअर्थी संवादों के असर से इतने वाकिफ होते हैं कि कई असली पीएचडी वाले उनका मुंह ताकें। ऐसे विशेषज्ञों को भरोसा होता है कि उनकी उछाली गई बात के अर्थों को लेकर कई गुट बनेंगे और उनमें वाक् युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे विद्वानों की सेवा ने सुमेरा की जुबान को निखारा है, धार प्रदान की है। बोली के पैनेपन को भोथरा होने से बचाने के लिए सुमेरा अक्सर बड़ी चतुराई के साथ अपनी जुबान को कुछ तीखे जुमलों के हवाले कर दिया करते हैं। बस, पैनापन और तेज हो जाता है।

सुमेरा कहा करते हैं कि भाषा, भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका है, जो बोला या लिखा जाता है। बिना बोले केवल हाव-भाव से भी संदेश संप्रेषित किए जा सकते हैं लेकिन सुमेरा का भरोसा बोलने में ज्यादा है। लिखनेवाले तो बहुत मिल जाते हैं, सुमेरा के पास भी हैं। पैसे और पॉवर से क्या नहीं हो सकता? और, 'भय बिनु होइ न प्रीत' का फॉर्मूला भी तो है। बोलना खुद पड़ता है। किसी और से कब तक बातें कराई जा सकती हैं? वे बत-बढ़ को बेअसर करने के लिए 'बातें हैं बातों का क्या' फॉर्मूला उछाल देते हैं, जिसके फॉलोअर्स की कमी नहीं। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए 'जितने मुंह उतनी बातें' तो है ही।

सुमेरा 'बात के धनी' ढूँढने निकले तो 'बात का बतंगड़' बनानेवाले, 'बात बिगाड़नेवाले' या 'बात हाँकने वाले' ज्यादा मिले, 'दो टूक बात' करनेवाले या 'बात रखनेवाले' कम मिले। बकौल कफ़ील आजर अमरोहवी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आजकल तो बात को सात समंदर पार जाने में टाइम नहीं लगता। भाषा की बात करते हुए बात से बात निकलती जा रही है क्योंकि भाषा और बातें अन्योन्याश्रित हैं। वैसे कई अवसरों पर भावनाओं और संवेदनाओं को अपना असर दिखाने के लिए भाषा के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। दार्शनिकों की मानें तो ईश्वर के साथ वार्तालाप के लिए मौन भाषा सबसे उपयुक्त होती है।आध्यात्मिक, वैचारिक, शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों में मौन व्रत रखने की शिक्षा दी जाती है। मितभाषी होना अवगुण नहीं। सो, एक दोहे से बात समाप्त करते हैं- कागा काको धन हरै, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाय के, जग अपनो करि लेत।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. मुकेश असीमित
लेखक व्यंग्यकार हैं।

सड़कछाप सड़क का दर्शनशास्त्र

सड़क का भी एक दर्शन होता है–खासकर उस सड़क का, जो खुद सड़कछाप हो। वह सड़क जो कहीं टिककर नहीं रहती, हर मोहल्ले, हर मोड़, हर चुनावी वादे में आवारगी करती मिल जाती है। आजकल ऐसी सड़कें खूब चलन में हैं–चलन में इसलिए कि चलने लायक कम और दिखने लायक ज़्यादा होती हैं।

सड़क साम्यवाद का जीवंत, धूल-धूसरित उदाहरण है। यहाँ गधे और घोड़े एक ही ताल में चलते हैं–कभी-कभी तो पहचान ही गड़बड़ा जाती है कि कौन सा किस श्रेणी में है। पशु, पक्षी, मानव–सबको सड़क समान भाव से अपनाती है। सड़क सबकी माँ है। अब अगर माँ की गोद में बैठकर कोई पूछे कि गधे-घोड़े का फर्क क्यों नहीं दिख रहा, तो इसमें माँ का क्या दोष! सड़क तो बस बनी है–आओ, चलो, दौड़ो, गिरो, रौंदो–जो लिखा लाए हो, वही होगा। आप सड़क पर हैं या सड़क पर लाए गए हैं–यह नियति का मामला है, सड़क का नहीं।

सड़क और संसद का रिश्ता भी बड़ा दार्शनिक है। आदमी कब सड़क से संसद पहुँच जाए और कब संसद से सड़क पर लौट आए–कहा नहीं जा सकता। जनता सड़क के रास्ते ही नेताओं को संसद का पता देती है और उसी रास्ते से वापसी का न्योता भी। इसलिए सड़क है तो संभावनाएँ हैं–धरने की, हड़ताल की, रैली की, जाम की, और कभी-कभी नंगे नाच की भी। सड़क लोकतंत्र की खुली प्रयोगशाला है।

सड़क है तो गड्ढे हैं। गड्ढे हैं तो मरम्मत है। मरम्मत है तो बजट है। बजट है तो फाइलें हैं। फाइलें हैं तो अफसर का चूल्हा जलता है। सड़क सरकार का बहुउद्देशीय औजार है–शौचालय, पेशाबघर और कचरा निस्तारण की कई योजनाओं से बचा लेती है। लोग सड़क पर ही अभ्यास कर लेते हैं, और सड़क 'राइट एट योर डोरस्टेप' कचरा सेवा दे देती है–बिना टेंडर, बिना उद्घाटन।

कोरोना के दिनों में जब सड़कें सूनी हुईं, तो उन्हें भी बुरा लगा। पर जल्दी ही फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को निकाला और सड़कें फिर गुलज़ार हो गईं। मजदूरों के रेलों ने सड़कों को धन्य कर दिया–माँ की गोद फिर भर गई।

सड़कें हैं तो एक्सीडेंट हैं। ट्रैफिक पुलिस का डंडा अभियान निरंतर है। चालान से जेबें भी फुल टॉस फूल रही हैं। सड़कें हैं तो फुटपाथ हैं, और

फुटपाथ हैं तो उन पर सोते लोग। वरना नशे में धुत रईसों को कुचलने के लिए लोग मिलेंगे कहाँ? सड़कें ही तो हैं जो रील और सेल्फी प्रेमियों की कर्मभूमि हैं–जहाँ जोखिम जितना बड़ा, व्यू उतने ज़्यादा। सड़कें हैं तो सड़कछाप गुंडे भी हैं। राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला यही है। रेहड़ियों से शुरू हुई हफ्तावसूली आगे चलकर बड़े घोटालों का पाठ्यक्रम बनती है। सड़क कैडर तैयार करती है–छुटभैये से गैंगस्टर तक।

आजकल सड़कों पर ध्यान कम है। ध्यान दें भी तो कैसे–सड़कें बड़ी बेवफ़ा हैं। बनाई नहीं कि उखड़ने को तैयार। इतना भी सब्र नहीं कि एक चुनावी कार्यकाल पूरा हो जाए। मरम्मत का बजट पास होते-होते नेता बदल जाता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। समाधान सरल है–हर नेता अपने नाम की सड़क बनवाए। चुनाव हार जाए तो सड़क उठाकर घर ले जाए।

सड़कें माँ जैसी हैं–बिल्कुल गाय की तरह। पान की पीक, कचरा, मल-मूत्र–सब समेट लेती हैं, बिना शिकायत। तभी तो आपने देखा होगा–गायें और उनके अधिकृत-अनधिकृत पतियों, यानी सांड–सड़क पर आराम से जुगाली करते हुए। स्टाफ का मामला है जी–जैसे रेलवे में टीटी अपने स्टाफ को सीट दिला ही देता है।

अब प्रश्न उठता है–माँ तो सड़क है, बाप कौन? हर कोई पूछता है, 'सड़क तेरे बाप की है क्या?' पर बाप का पता आज तक नहीं चला। मिलते ही सूचना दी जाएगी।

कभी-कभी सड़कें उधड़ती हैं ताकि शहर को ग्रामीण जीवन की झलक मिल सके–कंक्रीट, धूल, मिट्टी–ज़मीन से जुड़े रहने का प्रशिक्षण। चिकनी सड़क पर खेलेंगे तो बच्चों की इम्युनिटी कहाँ बनेगी?

सड़कें पतित-पावनी भी हैं–मोक्षदायिनी। प्राचीन योगियों की परंपरा आज सड़कें निभा रही हैं–कहीं दुर्गम, कहीं अदृश्य, कहीं कीचड़, कहीं खाई। हैं भी, नहीं भी–ब्रह्मस्वरूप। फाइलों में हैं, वादों में हैं, पर चलने में अक्सर नहीं। न शुरुआत दिखती है, न अंत। कोई पूछे, 'यह सड़क कहाँ जाती है?'–भाग्यशाली हैं वे जिनकी जाती है। यहाँ तो सालों से देख रहे हैं–नज़र ही नहीं आती।

सड़कें वही हैं–जहाँ चाहो मोड़ लो, बिना शिकायत। और अगर सरकारी बजट की हों, तो नेता जी उन्हें अपने बंगले तक भी ले जा सकते हैं। सड़कछाप सड़क–बस महसूस करने की चीज़ है। मानने की, जानने की नहीं।

कानून और न्याय
विचारणीय सवाल
विनय झैलावत
पूर्व असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता

सेमिनार में शामिल होना क्या वैचारिक पूर्वाग्रह का संकेत!

यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के कार्डिनल सिद्धांत से पैदा हुई है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा, क्योंकि एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करें। यह न्याय की निष्पक्षता और पवित्रता को सुनिश्चित करता है।

इन दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक रिक्युजल आवेदन चर्चा में है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी प्रत्यर्थियों की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर अपने मुख्यमंत्री काल में शराब के ठेके देने में कमीशन वाले मामले में दोषमुक्ति के खिलाफ सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को स्वयं को उनके प्रकरण से अलग करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह एक औपचारिक आवेदन होता है, जो संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है। इसका आधार यह है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता आरएसएस के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में शामिल हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और चार अन्य लोगों द्वारा दायर उन याचिकाओं का विरोध किया, जिनमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग की गई। अपने हलफनामे में एजेंसी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा वैचारिक रूप से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विधिक शाखा है। एजेंसी ने तर्क दिया कि अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित सेमिनार में शामिल होना किसी भी वैचारिक पूर्वाग्रह का संकेत नहीं है।

हलफनामे के अनुसार किसी न्यायाधीश पर सिर्फ इसलिए पूर्वाग्रह का आरोप लगाना कि उन्होंने गैर-राजनीतिक कानूनी सेमिनारों में हिस्सा लिया, बेबुनियाद है। यह न्यायालय के अधिकार को कम करने और न्याय प्रशासन में दखल देने की कोशिश के समान है। यह संभावित रूप से न्यायालय की अवमानना भी हो सकती है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अगर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के किसी कार्यक्रम में शामिल होना किसी न्यायाधीश के वैचारिक पूर्वाग्रह को दिखाता है, तो बड़ी संख्या में मौजूदा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना पड़ेगा, जिसमें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति आरोपी हों। सीबीआई ने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले में नामजद लोगों के पक्ष में भी आदेश दिए हैं।

सीबीआई ने उन आरोपों पर भी आपत्ति जताई कि न्यायमूर्ति शर्मा इस मामले की सुनवाई जल्दबाजी में कर रही हैं। सीबीआई के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटारा तेजी से किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले का हवाला भी दिया, जिसकी सुनवाई भी न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ही कर रही हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि इस मामले में, न्यायालय ने तीन महीने से भी कम समय में 27 सुनवाई की हैं। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसलों पर प्रथमदृष्टया टिप्पणी करने और आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने में कोई गलती नहीं की है।

यह उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरूण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायत ने न्यायमूर्ति शर्मा से खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए अर्जी प्रस्तुत की है। अरविंद केजरीवाल 6 अप्रैल को खुद उच्च न्यायालय में पेश हुए थे और अपनी अर्जी के संबंध में कुछ बातें रखी थीं। उन्होंने कहा कि वह न्यायाधीश को सुनवाई से अलग करने की अर्जी पर खुद ही बहस करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी अर्जी फाईल क्यों की है? यह जानना आवश्यक है कि आखिर क्या होता है न्यायाधीशों को खुद को सुनवाई से अलग करना?

यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के बीच मतभेद के कारण आधिकारिक कार्रवाई जैसे कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से अलग रहने से संबंधित है। इसमें न्यायाधीश स्वविवेक से निर्णय लेते हैं कि उन्हें सुनवाई करनी चाहिए अथवा नहीं। पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाला कोई औपचारिक नियम नहीं है। इसका आशय मात्र यह है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। यह एक गंभीर प्रक्रिया है और इसका उपयोग केवल ठोस आधार पर ही किया जाना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है। रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करना है।

न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं। खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारणों में हितों का टकराव भी होता है। यदि ऐसा लगता है तो एक न्यायाधीष मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का निर्णय करते समय पक्षपात किया है। हितों का टकराव भी कई तरह से हो सकता है। जैसे मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होना। किसी विषिष्ठ मामले में न्यायाधीष की भागीदारी कब और कैसे बाहर रखा जाना चाहिए, जहां उसका कोई हित हो, इस प्रथा पर संयुक्त राज्य अमेरिका और युनाईटेड किंगडम की स्थापना के बाद से ही इस पर गरमा गरम बहस होती रही है।

साथ ही किसी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लिये पेश वकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार भी इसका आधार हो सकता है। उच्च न्यायालय के ऐसे फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, जिस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तब निर्णय लिया गया जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। किसी कंपनी के ऐसे मामलों में भी जिसमें उसके शेयर हो। तब भी जब उसने अपने हित का खुलासा नहीं किया हो और इसमें कोई आपत्ति ना हो। यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के कार्डिनल सिद्धांत से पैदा हुई है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा। क्योंकि, एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करें।

सामान्यतः सुनवाई से अलग होने का फैसला न्यायाधीश खुद करता है। यह हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करने के लिए न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखिक रूप से खुद को अलग करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ कालानुक्रमिक क्रम में कारण बताते हैं। कुछ परिस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है। हालांकि, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां न्यायाधीशों ने विरोध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इंकार कर दिया। लेकिन, केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इंकार कर दिया। यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी कई चिंताएं विद्यमान हैं। यह न्यायिक स्वतंत्रता को कम करने का एक कदम भी माना जाता है। क्योंकि, यह पक्षकारों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक निष्पक्षता को कम करता है। साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों को कमजोर करता है। चूंकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नियम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएं हैं। कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच सुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने के लिए एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का विरोध करना चाहिए, चाहे वह कहीं से भी हो और यदि वे विचलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए एक नियम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

जलियांवाला बाग
दिलीप कुमार पाठक
लेखक पत्रकार हैं।

आज़ादी की वो कीमत, जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा

अमृतसर का वह छोटा सा मैदान, जिसे दुनिया आज 'जलियांवाला बाग' के नाम से जानती है, महज़ ईंट-पत्थरों का बना कोई स्मारक नहीं है। वह गवाह है उस अमानवीय बर्बरता का जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वह प्रतीक है उस अटूट हौसले का जिसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की नींव रख दी थी। बैसाखी का पावन दिन था। पंजाब के गाँवों और शहरों में उत्सव का माहौल होना चाहिए था। लोग नए कपड़े पहनकर मेलों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अमृतसर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पूरा देश 'रोलेट एक्ट' जैसे काले कानून के खिलाफ गुस्से में उबल रहा था, जिसने बिना दलील और बिना वकील के किसी को भी जेल भेजने की ताक़त अंग्रेज़ों को दे दी थी। इसी अन्याय के खिलाफ अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ दर्ज कराने के लिए शाम के वक्त करीब बीस हज़ार लोग उस बाग में इकट्ठा हुए थे।

इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो स्याही से नहीं, बल्कि इंसानी लहू से लिखी जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 की वह मनहूस शाम भी एक ऐसी ही तारीख थी, जिसने न केवल पंजाब की मिट्टी को लाल किया, बल्कि सोए हुए समूचे हिंदुस्तान की सोई हुई आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। अमृतसर का वह छोटा सा मैदान, जिसे दुनिया आज 'जलियांवाला बाग' के नाम से जानती है, महज़ ईंट-पत्थरों का बना कोई स्मारक नहीं है। वह गवाह है उस अमानवीय बर्बरता का जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वह प्रतीक है उस अटूट हौसले का जिसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की नींव रख दी थी। बैसाखी का पावन दिन था। पंजाब के गाँवों और शहरों में उत्सव का माहौल होना चाहिए था। लोग नए कपड़े पहनकर मेलों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अमृतसर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पूरा देश 'रोलेट एक्ट' जैसे काले कानून के खिलाफ गुस्से में उबल रहा था, जिसने बिना दलील और बिना वकील के किसी को भी जेल भेजने की ताक़त अंग्रेज़ों को दे दी थी। इसी अन्याय के खिलाफ अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ दर्ज कराने के लिए शाम के वक्त करीब बीस हज़ार लोग उस बाग में इकट्ठा हुए थे। उस विशाल भीड़ में मासूम बच्चे थे, अपने परिवारों के साथ आई महिलाएँ थीं और वे बुज़ुर्ग भी थे जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद सुस्ताने के लिए वहाँ रुके थे।

किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल साबित होने वाले हैं। शाम के करीब सवा पांच बज रहे थे, जब अचानक जनरल रेजिनल्ड डायर अपने नब्बे सशस्त्र सैनिकों के साथ उस बेहद संकरे रास्ते से दाखिल हुआ, जो बाग के अंदर आने और बाहर जाने का एकमात्र मार्ग था। उसने न तो भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी दी और न ही शांति की कोई अपील की। उसने बस पत्थर दिल होकर एक क्रूर आदेश दिया–'फायर!' अगले दस मिनट तक जो मंजर वहाँ दिखा, वह मानवता के इतिहास पर सबसे गहरा और बदनुमा कलंक था। सैनिकों की रायफलें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि उनकी आखिरी गोली खत्म नहीं हो गई। बाग की दीवारें सात-आठ फीट ऊँची थीं और एकमात्र निकास द्वार पर मौत का पहरा था। लोग बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के सिपाही जानबूझकर उन्हीं को निशाना बना रहे थे। चीख-पुकार, धुएँ और मलबे के बीच, अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में सैकड़ों लोगों ने उस पुराने कुएं में छलांग लगा दी, जिसे आज हम श्रद्धा से 'शहीदी कुआं' कहते हैं। देखते ही देखते वह कुआं लाशों से पट गया। सरकारी रिकॉर्ड्स भले ही मरने वालों की संख्या 379 बताते हों, लेकिन हकीकत यह थी कि उस शाम हज़ारों घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए थे।

इस जघन्य हत्याकांड ने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। यह वह ऐतिहासिक मोड़ था जहाँ से अंग्रेज़ों की भारत से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हुई। इस घटना के विरोध में गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी का वह विश्वास पूरी तरह टूट गया जो वे कभी अंग्रेज़ी न्याय प्रणाली में रखते थे। जलियांवाला बाग के इसी खूनी मंजर ने एक 15 साल के किशोर 'ऊधम सिंह' के भीतर प्रतिशोध का ऐसा लावा भरा कि उन्होंने 21 साल तक इस अपमान की आग को अपने सीने में जलाए रखा। अंततः साल 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर उन्होंने जनरल ओ डायर को मौत के घाट उतारा और दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान अपने शहीदों का अपमान कभी नहीं भूलता।

यह जलियांवाला बाग ही था जिसने भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों के दिलों में आज़ादी का बीज बोया। कहते हैं कि भगत सिंह इस घटना के बाद कई मील पैदल चलकर यहाँ आए थे और इस बाग की खूनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर ले गए थे, ताकि वह उन्हें हर पल गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की याद दिलाती रहे। आज, जब हम आज़ादी की खुली हवा में गर्व से सांस लेते हैं, तो हमें उन दीवारों की ओर एक बार ज़रूर देखना चाहिए जो आज भी गोलियों के निशानों को अपनी छाती पर लिए खड़ी हैं। वे निशान आज भी हमसे यह सवाल करते हैं कि जिस अखंड और मज़बूत भारत के लिए उन्होंने अपना सीना छलनी करवाया था, क्या हम आज उस विरासत को संभाल पा रहे हैं? 13 अप्रैल का यह दिन केवल इतिहास को दोहराने या शोक मनाने का नहीं है, बल्कि यह खुद के भीतर झाँकने और अपनी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों को समझने का दिन है। उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम देश की एकता और अखंडता को किसी भी संकीर्ण सोच की भेंट न चढ़ने दें। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी पवित्र है क्योंकि उसमें हमारे पुरखों का पसीना और लहू एक साथ मिला हुआ है। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि जिस आज़ादी का उत्सव हम मनाते हैं, उसकी जड़ें उसी बाग की नम और खूनी मिट्टी में कहीं गहरी धँसी हुई हैं। हिंदुस्तान उस महान बलिदान को कभी नहीं भूल सकता, और एक सजग नागरिक के तौर पर हमें भी इसे कभी विस्मृत नहीं होने देना चाहिए।

पर्व विशेष
श्वेता गोयल
लेखक शिक्षक हैं।

भारतीय आत्मा के पुनर्जागरण का पर्व है बैसाखी

भारत की मिट्टी केवल अन्न नहीं उपजाती बल्कि उत्सव, पराक्रम और त्याग की गाथाएं भी रचती है। भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र में, जहां लोक-जीवन ऋतुओं के चक्र के साथ कदमताल करता है, 'बैसाखी' भारतीय आत्मा के पुनर्जागरण का पर्व है। यह पर्व उस समय आता है, जब प्रकृति अपना श्रृंगार पूर्ण कर चुकी होती है और किसान की मेहनत स्वर्ण-कणों (गेहूं की फसल) के रूप में खेतों में लहलहाने लगती है। लेकिन बैसाखी का फलक केवल कृषि तक सीमित नहीं है; यह कृषि से शुरू होकर 'खालसा' के शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान तक विस्तृत है। बैसाखी का पर्व भारतीय जनमानस की आत्मा, विशेषकर किसान के पसीने की खुशबू और सिखों के गौरवशाली इतिहास का एक अनूठा संगम है।

कृषि प्रधान भारत में बैसाखी का सीधा और गहरा संबंध फसलों के पकने और प्रकृति के उल्लास से है। जब चैत्र मास की विदाई होती है और वैशाख का आगमन होता है, तब पंजाब और हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां हवा के झोंकों के साथ झूमने लगती हैं। यह किसान की साल भर की मेहनत के सफल होने का प्रतीक है। किसान जब अपनी लहलहाती फसल को देखता है तो उसका हृदय कृतज्ञता और उल्लास से भर जाता है। यही वह क्षण होता है, जब ढोल-नगाड़ों की थाप पर पंजाब के गबरू और मुटियारे भांगड़ा और गिद्दा के रूप में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। पारम्परिक पोशाकों की रंगीनी और गुरुद्वारों में जलने वाली दीपमालाएं इस पर्व को एक अलौकिक आभा प्रदान करती हैं।

यद्यपि बैसाखी को विशेष रूप से पंजाब का त्योहार माना जाता है परंतु वास्तव में इसकी जड़ें संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई हैं। यह पर्व भौगोलिक सीमाओं को लांघकर देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी विशिष्ट पहचान के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत की भांगड़े की गूंज जहां इसे ऊर्जा से भर देती है, वहीं पश्चिम बंगाल में इसे 'नबा वर्ष' या 'पोइला बैसाखी' के रूप में नव वर्ष की शुरुआत मानकर मनाया जाता है। दक्षिण भारत के केरल में यही पर्व 'विशू' के नाम से जाना जाता है, जहां लोग समृद्धि की कामना के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। असम के सुदूर क्षेत्रों में यह 'बिहू' की सुरीली धुनों में समाहित हो जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यह दिन अत्यंत पवित्र है क्योंकि हजारों साल पहले इसी तिथि पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यही कारण है कि इस दिन गंगा के तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और पवित्र नदियों में स्नान कर दान-पुण्य की परंपरा निभाई जाती है।

बैसाखी का धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष जितना समृद्ध है, इसका ऐतिहासिक पक्ष उतना ही गौरवशाली और साथ ही मर्मस्पर्शी भी है। सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सन् 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब में 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एक ऐसे समाज की रचना की, जो निर्भय, अनुशासित और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हो। गुरु जी ने 'पंच प्यारों' के माध्यम से मानवता को यह संदेश दिया कि बलिदान ही राष्ट्र और धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा मार्ग है। इसीलिए सिख समुदाय के लिए यह दिन केवल फसल का उत्सव नहीं बल्कि उनके आत्म-सम्मान और शौर्य के पुनर्जन्म का दिन है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी की खुशियों पर एक काले साये की तरह दिखाई देता है। अमृतसर का जलियांवाला बाग आज भी उन अनगिनत शहीदों की चीखों का साक्षी है, जिन्होंने रोलट एक्ट जैसे काले कानून के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर हजारों निहत्थे भारतीय वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे लेकिन जनरल डायर की क्रूरता ने बैसाखी के उत्सव को रक्त रंजित कर दिया। बिना किसी चेतावनी के चलाई गई अंधाधुंध गोलियों ने सैंकड़ों भारतीयों के सीने छलनी कर दिए। यह हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की चरम सीमा थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। बाद में वीर उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लिया, जो बैसाखी के प्रति एक क्रांतिकारी श्रद्धांजलि थी।

ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बैसाखी का विशेष महत्व है। बैसाखी का दिन एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का सूचक है। इस दिन सूर्य अपनी प्रथम राशि मेष में प्रवेश करता है, जिसे 'मेष संक्रांति' कहा जाता है। यह वह समय होता है, जब सूर्य अपनी कक्षा के उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिससे शीत ऋतु का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है, प्रकृति में नवजीवन का संचार होने लगता है और ग्रीष्म का आगमन होता है। सौर वर्ष के इस आरंभ को समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह दिन कालचक्र के नवीन आरंभ का सूचक है। अंततः, बैसाखी केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि यह संघर्ष, संस्कृति और समर्पण का अद्भुत समागम है। यह पर्व हमें यही संदेश देता है कि जहां परिश्रम का सम्मान है, वहां उल्लास का वास होता है; जहां अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस है, वहां खालसा का वास होता है और जहां राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वहां बलिदान की अमर गाथाएं लिखी जाती हैं। यह पर्व हमें गुरु गोबिन्द सिंह जी जैसे महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारने और राष्ट्र में शांति, सद्भावना तथा भाईचारे के नए युग की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और समाज के कल्याण हेतु सार्थक पहल करने का संदेश देता है। बैसाखी आई, खुशियां लाई, फसलों की रंगत छाई। नमन उन शहीदों को, जिन्होंने आजादी की अलख जगाई।

बैतूल-इटारसी के बीच बचे 21 किमी में नहीं मिल रही सुविधाएं

बैतूल। बैतूल-इटारसी फोरलेन के बरेठा घाट सेक्शन सहित 21 किमी में फोरलेन निर्माण होना शेष है। ऐसे में फोरलेन पर मिलने वाली सुविधाएं भी इस जगह उपलब्ध नहीं हो रही है। खासकर वाहनों के पलटने या दुर्घटना के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बनाने और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सडक़ से हटवाने के लिए इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम नहीं है। क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन जैसी कोई व्यवस्था यहां नहीं मिल रही है। यदि फोरलेन के 21 किमी निर्माण से बचे, इस हिस्से में कोई वाहन पलटता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वाहन यथावत पड़े रहते है या संबंधित थाना या विभाग द्वारा वाहनों को हटाया जाता है। कई बार बड़े-बड़े ट्रक पलटने के बाद 12 से 24 घंटे तक सडक पर ही पड़े रहते है। जिससे आने-जाने वाले वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से बार-बार जाम की स्थिति निर्मित होती है, वह अलग है। बताया जा रहा है कि इस हिस्से में फोरलेन का काम नहीं होने के कारण यहां पर इंसिडेंट मैनेजमेंट की क्रेन, एंबुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन तैनात नहीं रहता है, जबकि इस 21 किमी के रास्ते में हादसे और वाहनों के पलटने जैसी दुर्घटनाएं अक्सर सामने आती है। घायलों को भी इस सुनसान जंगल क्षेत्र में मदद मिलने में परेशानी होती है।

जाम के कारण घोड़ाडोंगरी होते हुए बैतूल पहुंचते है वाहन- कई बार सडक़ पर वाहनों के पलटने की घटना के बाद लंबा जाम भी लग जाता है। जिसकी वजह से कई बार वाहन चालक बरेठा से घोड़ाडोंगरी होते हुए बैतूल पहुंचते है और यहां से फिर हाइवे पकड़ते है। जिससे उन्हें लंबा फेरा भी लगाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि फोरलेन पर इटारसी-बैतूल के बीच जो यह 21 किमी का काम शेष बचा है, इस मार्ग पर ही सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर वाहन पलटने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर तत्काल राहत नहीं मिल पाती है। यदि यह हिस्सा भी फोरलेन में शामिल हो जायेगा तो वाहन चालकों को फोरलेन पर मिलने वाली सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। खासकर वाहन पलटने पर क्रेन या दुर्घटना होने पर तत्काल एंबुलेंस की सुविधा मिलने लगेगी।

बरेठा घाट पर तीन साल में 78 दुर्घटनाएं- बरेठा घाट सेक्शन सडक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां संकरी और घुमावदार दो-लेन सडक, ढलान और सीमित दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि बरेठा घाट पर 2022 से 2024 के बीच 51 सडक़ दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2025 में भी यहां 27 से अधिक दुर्घटनाएं हुई। अब तो यहां पर हर दिन 3 से 4 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी वजह से इस हिस्से का उन्नयन बेहद जरूरी माना जा रहा है। एनएचएआई ने इस सेक्शन के लिए जो नया प्लान तैयार किया है, उसमें घुमावदार रास्तों को सुधारा जाएगा और ब्लैक स्पॉट्स का स्थायी समाधान किया जाएगा। सबसे खासबात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत 10 एनिमल अंडरपास और 1 एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे, ताकि टाइगर सहित अन्य वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित न हो। साथ ही क्रैश बैरियर, रंबल स्ट्रिप, साइन बोर्ड, फेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे।

नागपुर-भोपाल हाइवे पर बरेठा 21 किमी बचा शेष- नागपुर-भोपाल जैसी दो बड़े महानगरों को जोडने वाले नेशनल हाइवे पर अब तक अवरोध बैतूल जिले में स्थित बरेठा घाट बचा है। भोपाल और नागपुर के बीच आवागमन को सुगम और तेज करने के लिए वैसे तो कई साल पहले बैतूल से नागपुर और बैतूल से भोपाल के लिए फोरलेन नेशनल हाईवे को एक साथ मंजूरी मिली थी। इसमें से बैतूल से नागपुर तक 173.3 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे (एनएच-47) बहुत पहले बन कर तैयार हो चुका। इसके विपरीत बैतूल से इटारसी के बीच 21 किमी के क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट की रोक थी। नागपुर (महाराष्ट्र) के

हाईकोर्ट में दायर पीआईएल के बाद से रूका है काम

इटारासी-बैतूल के माध्यम बरेठा घाट का लगभग 21 किलोमीटर का भाग शेष रह गया था। इसमें केसला रेज, भौरा रेंज तथा बरेठा घाट के तीन खंड (कुल 20.91 किमी) सम्मिलित है। ये सभी खंड वन्यजीव, विशेषकर टाइगर मुवमेंट कॉरिडोर के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इसी के चलते इन खंडों में निर्माण कार्य को 1 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्टे आदेश के पश्चात स्थगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न वैधानिक एवं पर्यावरणीय विशेष रूप से वन्यजीव संबंधों मंजूरियों की आवश्यकता थी। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एनएचएआई ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप पूरी कर ली है। प्रोजेक्ट के लिए वाइल्ड लाइफ बोर्ड एवं केन्द्र सरकार से सभी आवश्यक मंजूरिया प्राप्त हो चुकी है। अब उच्च न्यायालय द्वारा स्टे के औपचारिक रूप से हटने के संबंध में आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही न्यायालय से इसे संबंध में निर्देश प्राप्त होंगे, एनएचएआई द्वारा शेष बचे सेक्शन में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

इनका कहना है -

बरेठा घाट सेक्शन में इंसिडेंट मैनेजमेंट की टीम नहीं है। इस कारण वाहनों को हटवाने की व्यवस्था फिलहाल यहां पर नहीं है। यहां इस 21 किलोमीटर में काम पूरा होने के बाद यहां टीम नियुक्त की जा सकेगी। वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने पर हम व्यवस्था बनाते हैं।

- मनीष मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय डॉ. अम्बेडकर जयंती समारोह आज

धार। धार जिले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 13 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा। यह कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा।

सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पी.जी. कॉलेज धार के ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया है। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें बाबा साहब के जीवन दर्शन और उनके योगदान पर केंद्रित विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।

विकासखण्ड स्तर पर भी होंगे कायक्रम- जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के समस्त विकासखण्ड मुख्यालयों पर भी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती का उत्साहपूर्वक आयोजन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा

14 अप्रैल को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में निकलेगी भव्य पदयात्रा

धार। धार जिले में 10 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह 25 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जिले में यह पखवाड़ा कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में होगी पदयात्रा

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुभाष जैन ने बताया कि पखवाड़े के अंतर्गत 14 अप्रैल को शाम 4 बजे विशाल नारी शक्ति पदयात्रा (रैली) का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा लालबाग परिसर से प्रारंभ होगी, जिसमें राज्य मंत्री, भारत सरकार, सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। इस पदयात्रा में समाज की प्रबुद्ध महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है।

विविध रचनात्मक गतिविधियों का होगा आयोजन

अभियान के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं के साथ-साथ युवा वर्ग द्वारा नारी शक्ति वंदन दीवार तैयार की जाएगी, जिस पर सशक्तिकरण के संदेश अंकित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों में गोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित होंगे। धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों में व्याख्यान कार्यक्रम होंगे। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विषय आधारित चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।

अम्बेडकर जयंती पर विशेष ग्राम सभा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही उपस्थित जनसमूह को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों की होगी सहभागिता

महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संपूर्ण कार्यक्रम का नोडल विभाग बनाया गया है। इन सम्मेलनों में महिला सांसद, विधायक, महापौर, जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, महिला उद्यमी और स्व-सहायता समूहों की सदस्यों सहित लखपति दीदियों को आमंत्रित किया गया है ताकि उनके अनुभवों से अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिल सके।

सोहागपुर पुलिस थाने में तनाव मुक्ति योग का आयोजन

सोहागपुर। नवीन पुलिस थाना परिसर में मध्यप्रदेश पुलिस एवं हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में तनावमुक्ति योग का आयोजन किया गया।इस अवसर पर हार्टफुलनेस संस्थान के समन्वयक मोनिका दीक्षित एवं मनीष दीक्षित ने प्रति रविवार की भांति इस रविवार

भी प्रातः थाना परिसर में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को रोजमर्रा की भाग दौड़ से राहत, चिंता से मुक्ति काम एवं जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए तनाव मुक्त मन संवेदनशील पुलिसिंग का सशक्त संकल्प एवं पूरे सप्ताह की चुनौती पूर्ण ड्यूटी के लिए 30 मिनट का मानसिक कवच का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर हार्टफुलनेस संस्थान के अतिथियों ने रोजमर्रा के कामकाज पर सारगर्भित उद्बोधन करके आवश्यक जानकारी दी।

सेवानिवृत्त प्राचार्य महेश पचौरी पंचतत्व में विलीन

बैतूल। सेवानिवृत्त प्राचार्य महेश पचौरी आज रविवार की शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका देहावसान सुबह करीब 6 बजे हो गया था। इसके बाद शाम 4.30 बजे उनकी अंतिम यात्रा विकास नगर स्थित निवास से निकली। करीब 5.30 बजे कोठीबाजार मोक्षधाम में उनके अनुज भ्राता वरिष्ठ पत्रकार संजय पचौरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान शहर के सभी समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद थे। पर्यावरण और गाय के प्रति पचौरी परिवार की प्रतिबध्दता को देखते हुए गौ काष्ठ से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी तेरहंवी और श्रध्दांजलि सभा का आयोजन आगामी 24 अप्रैल को रखा

गया है। 82 वर्षीय महेश पचौरी प्रसिद्ध समाजसेवी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व वालीं सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती शंकुतला पचौरी के पति थे। उनकी चार पुत्रियां कनिका, निमिषा, विपाशा और तूलिका हैं। स्व. महेश पचौरी वरिष्ठ पत्रकार संजय व्दिवेदी के ससुर भी थे।

शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रभावी प्रदर्शन

सोहागपुर। अध्यापक एवं शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय पर शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यापक संघ अध्यक्ष उमेश ठाकुर के नेतृत्व में इस प्रर्दशन में सैकड़ों मातृशक्ति शिक्षिकाओं सहित शिक्षक शामिल हुए। शामिल हुए शिक्षकों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचे। यहां नायब तहसीलदार नीरू जैन को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में श्री ठाकुर ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की अनिवार्यता समाप्त करने एवं नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने के संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। जिसमें आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय एवं आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नॉन-टेट शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2010 की कंडिका 4 (क), (ग) एवं कंडिका 5

के अनुसार क्रमशः-

03 सितंबर 2001 के पश्चात नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक)03 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य गुरुजी से संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षक को टेट से छूट प्रदान की गई है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी उक्त छूट का उल्लेख किया गया है। इसकेबावजूद विभागीय आयुक्तों द्वारा समस्त सेवारत नॉन- टेट शिक्षको को टेट उत्तीर्ण करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि अधिसूचना के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की भावना के विपरीत कार्य किया जा है।अतः मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जा रहा है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा दिनांक 02 मार्च 2026 तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। श्री ठाकुर ने अंत में बताया कि इस आदेश से प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों में टेट की अनिवार्यता के कारण मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों श अनावश्यक मानसिक तनाव से राहत प्रदान करने की कष्ट करें। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की लंबे समय से की जा रही ज्वलंत मांग को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से किए जाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करें। जिससे पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण जैसे वैधानिक लाभ पदोन्नति , क्रमोन्नति की भांति सुनिश्चित हो सके। शिक्षक आश्वस्त हैं कि इस विषय पर संवेदनशीलता एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते आवश्यक राहत प्रदान करेंगें।

मानवी विहाल की हैट्रिक से सरदारपुर एफसी ने जबलपुर एकादश को 3-0 गोल से हराया

जूनियर बालिका राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता में सरदारपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

धार। जबलपुर में खेली जा रही जूनियर बालिका राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता में सरदारपुर एफसी ने धार जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए सेमीफाइनल मैच में सशक्त जबलपुर को मानवी विहाल की हैट्रिक की सहायता से 3 - 0 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कोच शेलेन्द्र पाल ने बताया कि सरदारपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सुसज्जित सरदारपुर एफसी (डीएफए धार) की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जबलपुर को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

सरदारपुर एफसी (डीएफए धार) की टीम ने अपने पहले मैच में डीएफए मुरैना को 9 - 0 से पराजित किया था। जिसमें मानवी विहाल ने डबल हैट्रिक सहित आठ गोल और प्रतिभा ने एक गोल किया था। प्रबंधक चंचल खराड़ी ने बताया सरदारपुर एफसी टीम की ओर से मानवी विहाल, प्रतिभा, गुनगुन शर्मा, कोमल ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और जीत में अहम भूमिका निभाई।

स्पर्धा का फाइनल मुकाबला 13 अप्रैल को सुबह खेला जाएगा। जिसमें सरदारपुर एफसी (डीएफए धार) और डीएफए मंडला के बीच खिताबी भिड़ंत होगी।

सरदारपुर एफसी (डीएफए धार) के शानदार प्रदर्शन पर पुलिस अधीक्षक एवं डीएफए अध्यक्ष मयंक अवस्थी, कार्यकारी अध्यक्ष शमशेर सिंह यादव, डीएफए सचिव सुभाष डेविड, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति चौहान, एसडीएम सलोनी अग्रवाल, सहायक आयुक्त नरोत्तम वरकड़े, संजय परमार ,आनंद पाठक, प्राचार्य जब्बर सिंह पटेल, डीएसओ राजेश शाक्य, आरआई पुरुषोत्तम बिश्नोई, राधेश्याम गढ़वाल,राजीव डेविड, शिवांग ग्रेवाल, दीपिका चौहान, संतोष चौहान, सुनीता भाबर ने हर्ष जताते हुए बधाई दी है।

थाना परिसर में मिलेगा शीतल पेयजल, वट वृक्ष के नीचे पक्षियों को दाना-पानी

सोहागपुर । जहां एक ओर आज की चकाचौंध में नागरिक दूसरों के लिए थोड़ा भी समय निकालनें में मुश्किल होती है। ऐसे में जब से नवीन पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में नवीन पुलिस थाना परिसर में आजकल गर्मियों में वट वृक्ष के नीचे पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस थाना परिसर में आने वाले आगुंतकों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। एएसआई गणेश राय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि इस गर्मी में अपने-अपने घरों अथवा कार्यालयों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। पक्षियों के पीने के लिए मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल हो। जिससे जल शीतल रहे।

विदा ले रहे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल, एडीजे पारस जैन ने धार के अधिवक्ताओं की प्रशंसा कर धार जिले में अपने कार्यकाल को यादगार बताया

नवागत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन स्वागत से अभिभूत, धार जिले में इसी प्रकार परस्पर सहयोग की जताई आशा

धार। धार जिला अभिभाषक संघ द्वारा नवागत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन के स्वागत एवं धार से सीहोर स्थानांतरित हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस जैन का विदाई समारोह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

जिला अभिभाषक संघ धार के अध्यक्ष हितेश ठाकुर एडवोकेट ने स्वागत भाषण में कहा कि धार जिला अभिभाषक संघ का अत्यंत गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है और जिस भावुक हृदय से हम आज स्थानांतरित हुए पी डी जे श्री अग्रवाल साहब को और ए डीजे पारस जैन साहब को विदाई दे रहे हैं नवागत पी डी जे मैडम को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि धार जिले में आगामी समय में भी बार और बेंच के संबंध हमेशा मधुर बने रह कर पक्षकारों को न्याय दिलाने में सफल रहेंगे।

समारोह को स्थानांतरित हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल एवं अपर जिला न्यायाधीश पारस जैन ने भी

संबोधित करते हुए अपने धार जिले में पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए धार जिले के अधिवक्तागण की प्रशंसा की तथा धार जिले में अपने कार्यकाल को यादगार बताया। समारोह को नवागत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है मुझे धार जिले में कार्य करने के दौरान आप लोगों से इसी प्रकार परस्पर सहयोग की आशा है। कार्यक्रम को जिले के प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस सुजावल जग्गा द्वारा भी संबोधित किया गया

स्वागत एवं विदाई के इस मिलेजुले कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव, विशेष जिला न्यायाधीश मेरी मार्गरेट मैडम सहित समस्त न्यायाधीशगण एवं समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे। समारोह के प्रारंभ में अतिथिगण का स्वागत अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हितेश ठाकुर, उपाध्यक्ष राकेश चौधरी, सचिव संतोष जाट, सहसचिव विनय प्रजापति, ग्रंथपाल विनोद नाभवंशी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण देवड़ा, महिला कार्यकारिणी सदस्य सुश्री दुर्गा मेरबानी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य प्रखर सोनी एवं मनोज परमार अधिवक्तागण द्वारा किया गया।

संघ अध्यक्ष हितेश ठाकुर द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ के सचिव संतोष जाट एडवोकेट द्वारा तथा आभार प्रदर्शन कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य प्रखर सोनी द्वारा किया गया।

कार्यालय जनपद पंचायत नालछा, जिला धार म.प्र.

क्र./1263 /मु.क.वि.यो./ 2026 नालछा दिनांक10/4/2026

विज्ञप्ति

जनपद पंचायत नालछा द्वारा दिनांक 20.04.2026 को जनपद पंचायत नालछा, तहसील पीथमपुर जिला धार में अनुमानित 200 जोडे का मुख्यमंत्री कन्या सामुहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

1 भोजन मीनु - पुडी, पापड़ कतरन, तली हुई मिर्ची, आलु टमाटर छोले की सब्जी, नुक्ती, पुलाव अनुमानित संख्या 3000 (तीन हजार व्यक्तियों की)।
2 टेन्ट व्यवस्था - 10 सौफे, 100 कुर्सिया कवर के साथ, 300 कुर्सिया सादी, दरी प्रति जोड़े के हिसाब से, 800 गददे एवं मंच लकड़ी का।
3 माईक व्यवस्था - साउण्ड, माईक एवं लाईट व्यवस्था मंच पुरे परिसर सहित मय जनरेटर व्यवस्था एवं ढोल तासे आदि।
4 स्वागत हेतु फुलमाला - संख्या 100 , वरमाला 400, गुलदस्ते 10, फूल 20 किलो।
5 विवाह कार्यक्रम - वीड़ियोग्राफी / फोटोग्राफी ।
6 विवाह कार्यक्रम- फ्लेक्स एवं प्रमाण-पत्र।
7 विवाह लग्न हेतु कुंड निर्माण समस्त प्रकार की पूजन सामग्री एवं पंड़ित व्यवस्था ।

इच्छुक निविदाकर्ता से सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17.04.2026 दोपहर 12ः00 बजे तक प्रत्येक बिंदु की पृथक-पृथक दरे प्रस्तुत करें। इसी दिनांक को दोपहर 02ः00 बजे निविदाये खोली जावेगी । (किसी भी प्रकार के लिये अंतिम निर्णय जनपद पंचायत नालछा का सर्वमान्य होगा)।

नोट- (सामग्री सम्मिलित होने वाले जोड़ो के हिसाब से घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में विज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी व इसकी सूचना 24 घण्टे पूर्व संबंधित को दी जावेगी) ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नालछा

संक्षिप्त समाचार

संयुक्त संचालक तृप्ति त्रिपाठी ने आंगनवाड़ियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बैतूल (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग नर्मदापुरम संभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी ने गुरुवार को बैतूल जिले के भीमपुर विकासखंड में आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम नांदा, पलासपानी, इमलीढाना और ग्वाडीढाना स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा कर वहां संचालित गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का अवलोकन करते हुए उन्होंने उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। संयुक्त संचालक श्रीमती त्रिपाठी ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में संचालित ईसीसीई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा गतिविधियों की भी समीक्षा की और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय भीमपुर में पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पोषण पखवाड़ा के प्रभावी आयोजन, योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति, पोषण ट्रैकर में हितग्राहियों के पंजीयन, आधार एवं आभा आईडी के सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने कुपोषित बच्चों को एनआरसी भीमपुर में भर्ती कराने तथा सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को 30 अप्रैल 2026 तक 'सक्षम आंगनवाड़ी 'के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किया जिला कोषालय का औचक निरीक्षण

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोषालय के डबल लॉक की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्री रूमसिंह डुडवे तथा सहायक कोषालय अधिकारी श्री बृजेश चौरे सहित कोषालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किया जिला कोषालय का औचक निरीक्षण

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोषालय के डबल लॉक की व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्री रूमसिंह डुडवे तथा सहायक कोषालय अधिकारी श्री बृजेश चौरे सहित कोषालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 4314 बालिकाओं का किया टीकाकरण

हरदा (निप्र)। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुक्रवार 10 अप्रैल तक जिले में कुल 4314 बालिकाओं को टीकाकरण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि हरदा में 620, टिमरनी में 826, खिरकिया में 841, सिराली में 494, रहटगांव में 525, हंडिया में 1008 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इस प्रकार जिले में कुल 6715 के लक्ष्य विरूद्ध 4314 कुल 64.24 प्रतिशत बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण किया गया। डॉ. सिंह ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी से होता है। एचपीवी टीका एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो कैंसर से बचाने में मदद करता है। यह टीका जिला चिकित्सालय हरदा तथा टिमरनी, सिराली, खिरकिया व हंडिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा रहटगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि ऐसी बालिकाऐं जिनकी आयु 14 वर्ष तथा 15 वर्ष 3 माह तक की है वे अपनी बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाएं।

जिले के सभी 240 उपार्जन केंद्रों पर उत्साह के साथ शुरू हुई गेहूं की खरीदी

535 किसानों से खरीदा गया 2247 मीट्रिक टन गेहूं

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले के सभी 240 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य उत्साह और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों का सम्मान किया गया और तौल कांटों का पूजन किया गया। जिला उपार्जन प्रभारी श्री आकाश चंदेल ने बताया कि 10 अप्रैल को शाम 05 बजे तक जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर 535 किसानों से 2247 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। इसके साथ ही अभी तक जिले के कुल 19,339 किसानों ने स्लॉट बुक किया है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया जा रहा है।

आयुष विभाग द्वारा शिविर लगाकर मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस

हरदा (निप्र)। होम्यापैथी के जनक हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर हैनीमैन जयंती पर प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर शुक्रवार को आयुष विभाग हरदा अंतर्गत होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चारखेड़ा एवं गहाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के निर्देश अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे आसपास के ग्रामो से लगभग 308 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर का शुभारम्भ ग्राम सरपंच एवं अन्य अतिथियो की उपस्थिति किया गया।

टीकाकरण ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय: विधायक डॉ पंडाग्रे

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारणी की छात्राओं को लगाई एचपीवी वैक्सीन

बैतूल (निप्र)। बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सारणी एवं शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सारणी में शुक्रवार को निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत संचालित है, जिसका उद्देश्य 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के संभावित लक्षण, इसके खतरे एवं एचपीवी टीकाकरण के महत्व के बारे में विस्तृत एवं सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को जागरूक करते हुए कहा कि समय पर टीकाकरण ही इस गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। विधायक डॉ. पंडाग्रे ने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक ' संजीवनी 'सिद्ध होगा और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अपनी 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को इस निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ दिलाकर उन्हें एक सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य प्रदान करें। कार्यक्रम के दौरान नपा अध्यक्ष किशोर बरर्दे, राजेश आहूजा, गोलू राजपूत, सुभाष चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के बेतवा सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विदिशा शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांकन कर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित परिवारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जतरापुरा क्षेत्र में अधिक संख्या में ऐसे बच्चे पाए जाने पर उनके स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करने एवं शिक्षा विभाग द्वारा सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही उक्त क्षेत्रों में सड़क, बिजली एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भिक्षावृत्ति करते पाए जाने वाले बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें छात्रावास में रखा जाए तथा उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) हेतु पात्र बच्चों के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, संप्रेक्षण गृह से कुछ दिन पूर्व भागी हुई दो बालिकाओं की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर महोदय ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, नियमित निगरानी बढ़ाने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इस लापरवाही के

लिए ड्यूटी के दौरान उपस्थित हाउस मास्टर, चौकीदार एवं पुलिस आरक्षक की सेवा समाप्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में समिति अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं जैसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, शिशु गृह, संप्रेक्षण गृह, वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड लाइन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति, संप्रेक्षण गृह, शिशु गृह एवं स्पॉन्सरशिप योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रोहित कासवनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओपी सनोडिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसबा, सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा सहित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रामबाबू प्रजापति एवं सदस्यगण चंद्रभान सिंह बघेल, श्रीमती सुनीता दांगी, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, श्री दीवान सिंह मीना उपस्थित रहे। किशोर न्याय बोर्ड से श्री प्रेम सिंह धाकड़, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी श्रीमती कृतिका व्यास एवं संप्रेक्षण गृह अधीक्षक श्रीमती आकांक्षा मरावी भी बैठक में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, RPF, SJPU सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत प्रशिक्षु कु. दिव्यांशी कुशवाह ने भोपाल में शुरू किया स्वरोजगार

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत भावना मेकअप स्टूडियो, गुलाबगंज से प्रशिक्षण प्राप्त कर कु. दिव्यांशी कुशवाह ने सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने ने बी कॉम कोर्स की शिक्षा प्राप्त की है। ब्यूटी एवं वेलनेस में रुचि होने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ब्यूटीशियन कोर्स में अप्लाई किया। भावना मेकअप स्टूडियो, गुलाबगंज में उन्हें अपनी रुचि से संबंधित प्रशिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में उन्होंने दिव्या ब्यूटी लाउंज नाम से खुद का ब्यूटी पार्लर भोपाल के बरखेड़ा पठानी में चालू किया है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 1200-1500 रुपए की आय हो रही है। इस आय से वे आपनी व्यक्तिगत खर्चों का वहन करने के साथ-साथ MBA की पढ़ाई व परिवार की आर्थिक सहायता भी कर रही हैं। कु. दिव्यांशी कुशवाह ने अपनी सफलता का श्रेय कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश को दिया है। उन्होंने विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के कारण ही उन्हें स्वरोजगार का यह अवसर मिला। यह उपलब्धि अन्य युवाओं युवतियों के लिए भी प्रेरणादायक है, जो तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं।

भैरूंदा के शासकीय संदीपनी स्कूल में आधार अपडेशन शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 'विद्यार्थियों के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार' अभियान के अंतर्गत भैरूंदा के शासकीय सांदीपनि विद्यालय में आधार अपडेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 40 विद्यार्थियों का आधार अपडेट किया गया। कैंप प्रभारी श्रीमती राधिका भावरेटा ने बताया कि विद्यालय स्तर पर इस प्रकार के शिविर आयोजित करने से विद्यार्थियों को समय पर आधार अपडेट की सुविधा मिल रही है, जिससे उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के आधार को समय-समय पर अपडेट कराते रहें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

संभागायुक्त ने ग्राम घाटपलासी एवं झरखेड़ा में किया अमरूद की खेती का निरीक्षण

अधिक से अधिक पात्र किसानों को दिलाया जाए उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ - संभागायुक्त

सीहोर (निप्र)। भोपाल संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने सीहोर जिले के ग्राम घाट पलासी में किसान श्रीमती शीला मीणा और उनके पति श्री श्यामलाल मीणा द्वारा उद्यानिकी विभाग की योजना के अंतर्गत की जा रही पिंक ताइवान किस्म की अमरुद की खेती का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान किसान श्रीमती शीला मीणा ने संभागायुक्त श्री सिंह को बताया कि वे अपनी 2.5 हैक्टेयर भूमि में इस किस्म के अमरूद की खेती कर रही हैं। इसी प्रकार संभागायुक्त ने ग्राम झरखेडा के किसान श्री सीताराम पाटीदार द्वारा 02 हैक्टेयर में की जा रही अमरूद की खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से अमरुद फसल उत्पादन तकनीक, बाजार व्यवस्था और फसल मूल्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें फसल विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के अधिक से अधिक पात्र किसानों को उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, ताकि किसान उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दें और जिले में उद्यानिकी का रकबा तथा किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो।

निरीक्षण के दौरान संयुक्त संभागायुक्त श्री विनोद यादव, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री सुनील रघुवंशी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला सामुदायिक संगठनों को सहकारिता अधिनियम का प्रशिक्षण

संचालन एवं प्रबंधन पर दिया गया मार्गदर्शन

विदिशा (निप्र)। महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला सामुदायिक संगठनों के लिए सहकारिता अधिनियम अंतर्गत एक दिवसीय समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभागार, विदिशा में किया गया। कार्यक्रम में मिशन के अंतर्गत गठित महिला सामुदायिक संगठनों को सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्यादित' के रूप में पंजीकरण उपरांत उनके सुचारू संचालन हेतु विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले के सभी विकासखंडों से लगभग 70 महिला सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों जैसे–निर्वाचन प्रक्रिया, आंतरिक एवं विभागीय ऑडिट, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन, अभिलेख संधारण (बुक्स ऑफ रिकॉर्ड) एवं बैंक खातों के संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही संस्थाओं के पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक संजय चौरसिया, सहायक प्रबंधक रवि कुमार चौकसे, सहकारिता विभाग के उपायुक्त ध्रुव कुमार झारिया तथा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक किशोर अहरवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिलाओं को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

एनएचआरसी के स्पेशल मॉनीटर ने सांची में शासकीय अस्पताल का किया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। ह्यूमन राइट कमीशन (एनएचआरसी) के स्पेशल मॉनीटर डॉ प्रदीप कुमार नायक द्वारा आज सांची में शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट को दी जा रही दवाइयों तथा नवीन चिन्हांकित लेप्रोसी मरीज और उपचाररत मरीजों को देखा। स्पेशल मॉनीटर डॉ प्रदीप कुमार नायक द्वारा कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा से मरीजों के उपचार के संबंध में चर्चा की गठ। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लेप्रोसी मरीज को दी जाने वाली विभागीय सुविधा के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर सीमएचओ डॉ दिनेश खत्री, बीएमओ डॉ रवि कुमार राठौर सहित अन्य डॉक्टर्स उपस्थित रहे।

जिले में सभी एसडीएम द्वारा उपार्जन केन्द्रों का किया गया निरीक्षण

रायसेन (निप्र)। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके परिपालन में शुक्रवार को एसडीएम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बेगमगंज विकासखण्ड के उपार्जन केन्द्र सीताराम वेयरहाउस तथा दिशांत वेयरहाउस का एसडीएम श्री सौरभ मिश्रा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान फसल विक्रय हेतु पहुंचे किसानों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। इसी प्रकार सिलवानी विकासखण्ड में उपार्जन केन्द्र श्रीजी वेयरहाउस पर जनपद पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थित में उपार्जन कार्य का शुभारंभ किया गया। औब्दुल्लागंज विकासखण्ड अंतर्गत उपार्जन केन्द्र माँ पार्वती वेयरहाउस ग्राम रोजड़ाचक में जनप्रतिनिधियों और एसडीएम द्वारा तौल कांटों की पूजन कर उपार्जन कार्य शुरू कराया गया। गैरतगंज विकासखण्ड अंतर्गत एसडीएम श्री अंकित जैन द्वारा उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. अंबेडकर के जीवन, विचारों और योगदान के बारे में जानकारी दी गई

डॉ. अंबेडकर की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल तक जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। इन कार्यक्रमों में डॉ. अंबेडकर के जीवन, विचारों, देश एवं लोकतंत्र के लिए उनके योगदान तथा संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका के बारे में बताया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, विधायक हरदा डॉ. आर.के. दोगने, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गेहलोत, जिला पंचायत सदस्य श्री ललित पटेल व श्री कमलेश सेजकर, जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी श्री प्रवीण इवने सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्राचार्य शासकीय सांदिपनी विद्यालय करताना श्री पी.सी. दांदरे एवं सहायक प्रध्यापक, आदर्श महाविद्यालय श्री संतोष कुमार राठौर ने प्रवक्ता के रूप डॉ. अंबेडकर के जीवन, विचारों, देश एवं लोकतंत्र के लिए उनके योगदान तथा संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई।

सीएमएचओ डॉ. एच.पी. सिंह ने उपस्थित जनों को सर्वाइकल कैंसर एवं एचपीवी वैक्सीन की जानकारी दी। उन्होने उपस्थित लोगों को 14 से 15 वर्ष तक बालिकाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में हरदा विधायक डॉ. दोगने ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि शासन द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर शासन की इन योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर का उद्देश्य था कि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो, हमें उनके इस उद्देश्य को पूरा करना है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह ने कहा कि आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए है जिन्हें देश के संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होने सभी को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गहलोत, जिला पंचायत सदस्य श्री कमलेश सेजकर व श्री ललित पटेल ने भी सभी को अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने राणा सांगा की जयंती पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के गौरव, अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह 'राणा सांगा' की जयंती पर पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राणा सांगा ने अपने अद्वितीय पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा की। त्याग व निष्ठा के लिए समर्पित उनका जीवन युवाओं को हर हाल में राष्ट्र सेवा करने का मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा।

सुरों और संगीत की प्रतिम साधिका थीं आशा भोसले

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रख्यात गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे सुरों और संगीत की अप्रतिम साधिका थीं। उन्होंने गायन के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की। वे अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की तरह बहुत योग्य और दक्ष गायिका थीं। शास्त्रीय संगीत और गायन का उन्होंने गहरा अभ्यास किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आशा भोसले ने अपने गायन करियर में कई दिग्गज कलाकारों के लिए गीत गाए। जिन भी अभिनेत्रियों के लिए उन्होंने गीत गाए उनको अपने अभिनय कैरियर में अपार सफलता मिली। श्रीमती आशा भोसले को पद्म विभूषण और दादासाहेब फाल्के जैसे बड़े अवॉर्ड मिले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में स्थान मिला।

मध्यप्रदेश सरकार ने दिया था राष्ट्रीय सम्मान

आशा भोसले ऐसी गायिका थीं जिन्हें मध्यप्रदेश शासन का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 1989-90 के लिए भी मिल चुका है। वे मध्यप्रदेश से बहुत लगाव रखती थीं। मध्यप्रदेशवासियों से उनका निरंतर संबंध रहा। वे यहां मंचीय प्रस्तुतियां देने के लिए आती रहीं। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में वे राजधानी भोपाल आई थीं। राज्य सरकार ने उन्हें विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों में आमंत्रित किया।

स्वर कोकिला आशा भोंसले ने अनगिनत पीढ़ियों के हृदय में स्थायी स्थान बनाया : शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संगीत जगत की अनुपम स्वर साधिका श्रीमती आशा भोंसले के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार अत्यंत पीड़ादायक है और भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आशा भोंसले की अद्वितीय गायकी, भावपूर्ण स्वर और बहुमुखी प्रतिभा ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी आवाज ने अनगिनत पीढ़ियों के हृदय में स्थायी स्थान बनाया है और उनके गीत सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका निधन केवल एक महान कलाकार का नहीं, बल्कि एक युग के अंत के समान है। संगीत जगत में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने और शोक संतप्त परिजन और असंख्य प्रशंसकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

सीएम ने श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी की जयंती पर किया पुण्य स्मरण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. भंडारी का संगठन के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का संकल्प जनसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय लालजी टंडन की जयंती पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल, श्रद्धेय लालजी टंडन 'बाबूजी' की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. टंडन का संगठन और जनसेवा के प्रति उनका समर्पित जीवन, हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है, जो हमें राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता रहेगा।

मध्य प्रदेश में मधुमक्खियों का तांडव

72 घंटे में 2 की मौत, अब गेहूं काट रहे किसान पर किया जानलेवा हमला

उमरिया (नप्र)। मध्य प्रदेश में इन दिनों मधुमक्खियों के हमले की खौफनाक खबरें आ रही हैं। इन खबरों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। उमरिया जिले में गेहूं की कटाई कर रहे एक वृद्ध किसान को मधुमक्खियों ने घेरकर मार डाला, वहीं 2 दिन पहले आगर मालवा में स्कूल के भीतर परीक्षा दे रहे बच्चों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें एक 9 वर्षीय मासूम की मौत हो गई।

मदद के लिए गुहार लगाता रहा किसान- उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के ग्राम पनपथा में 65 वर्षीय किसान गोविंद जायसवाल अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। पास ही एक बरगद के पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। बताया जा रहा है कि किसी पक्षी ने छत्ते पर चोंच मार दी, जिससे मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं। मधुमक्खियों के झुंड ने गोविंद पर हमला बोल दिया। खेत सुनसान जगह पर होने के कारण उनकी चीख-पुकार किसी ने नहीं सुनी और अत्यधिक डंक लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

आगर मालवा के स्कूल में अटैक- दूसरी ओर, आगर मालवा के सोयतकला स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में मातम छा गया। यहां बच्चे कक्षा में बैठकर परीक्षा दे रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों के तीन झुंड सक्रिय हो गए। हमले में कक्षा चौथी का छात्र रमन (9 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे झालावाड़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। करीब आधा दर्जन अन्य बच्चे भी घायल हैं। विजय सिंह पटले, थाना प्रभारी, इन्दवार (उमरिया)ने कहा उमरिया की घटना की जानकारी मिली है, लेकिन परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी घटनाओं में पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है ताकि वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

लापरवाही और सुरक्षा पर सवाल- उमरिया की घटना प्राकृतिक और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ थी, लेकिन आगर मालवा का हादसा सीधे तौर पर लापरवाही की ओर इशारा करता है। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने प्रशासन को छत्तों के बारे में बताया था, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के बैठने वाली जगह पर खतरा जानते हुए भी परीक्षा क्यों आयोजित की गई?

गोविंदपुरा इलाके में चलती स्कूटी के बराबर आकर खींचा बैग

दो महिलाएं सड़क पर गिरीं, मोबाइल-नकदी से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में स्थित पानी की टंकी के पास जेके रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने एक महिला से चलती स्कूटी पर बैग झपटने का प्रयास किया। इससे स्कूटी सवार महिला और उसकी सहेली सड़क पर गिरकर घायल हो गई।

दोनों को गंभीर चोट आई हैं, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। ऐशबाग और गोविंदपुरा थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

टीआई अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि किर्ती शर्मा और उनकी सहेली आंगनबाड़ी की आशा कार्यकर्ता हैं। दोनों पिपलानी में रहने वाली सहेली से मिलकर अपनी स्कूटी से शनिवार की रात को घर की ओर लौट रही थीं। पानी की टंकी के पास जेके रोड पर बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया।

मोबाइल और बैग झपटकर फरार हुए

एक युवक ने चलती बाइक पर महिला के बैग को झपटने का प्रयास किया। क्योंकि बैग क्रास में टंगा था, वह आसानी से नहीं खिंचा, लुटेरे ने जोर लगाया तो महिला जमीन पर गिर गई। जिसके बाद आरोपी बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में नकदी, मोबाइल और दस्तावेज रखे थे।

राहगीरों ने महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

तेज रफ्तार सीमेंट कैप्सूल वाहन ने 5 को कुचला, मौत

डिंडौरी (नप्र)। डिंडौरी-अमरकंटक मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 स्थित किकरा तालाब के पास बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी अपनी पिकअप का पंचर सुधार रहे आधा दर्जन लोगों को एक बेकाबू सीमेंट कैप्सूल वाहन ने बेरहमी से रौंद दिया। इस भीषण टक्कर में 5 ग्रामीणों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

आधी रात को पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, ग्राम परसवाह के रहने वाले ये लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। रात करीब 1 बजे उनकी पिकअप का टायर अचानक पंचर हो गया। गाड़ासरई थाना क्षेत्र में किकरा तालाब के पास सभी सड़क किनारे वाहन खड़ा कर पंचर सुधारने में जुटे थे, तभी करंजिया से लौट रहे कैप्सूल वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें चपेट में ले लिया।

घटनास्थल पर ही थम गईं 5 सांसें

वाहिनी सिंह, पुलिस अधीक्षक, डिंडौरी ने कहा हादसा इतना भीषण था कि वाहन के नीचे आए 5 लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताया कि मृतकों में 30 से 58 वर्ष की आयु के पुरुष शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया।

आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। घायलों को बेहतर उपचार और मृतकों के परिजनों को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्यसभा की उम्मीदवारी पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह बोले

हमें कोई नहीं चाहता, मैं दिन में सपने नहीं देखता

भोपाल (नप्र)। एमपी में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर दिग्विजय सिंह सांसद हैं। उनके तीसरी बार राज्यसभा जाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस में केंडिडेट को लेकर रेस चल रही है।

इस बीच राज्यसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा- सच्चाई ये है कि न तो हमें कोई चाहता है, न कुछ होना है। दिन में सपने गोविंद सिंह नहीं देखा करते।

कांग्रेस में कोई मंथन नहीं चल रहा

डॉ. गोविंद सिंह ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन को लेकर कहा -कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, यहां कोई मंथन नहीं चल रहा है। हाईकमान को उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष खरगे जी और राहुल जी जो निर्णय करेंगे, वही सर्वमान्य होगा। बीजेपी वाले तमाम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन असफल होंगे।

जनाधार वाले नेता को भेजा जाए राज्यसभा

डॉ. गोविंद सिंह ने कहा- जब पूरा निर्णय हमारे हाईकमान पर है, तो राय देना उचित नहीं है। हालांकि, हमारा मानना है कि ऐसे जनाधार वाले नेता को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, जो आम जनता और पार्टी के हित में काम करे और लोगों के सुख-दुख में साथ खड़ा रहे।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतिनिधि प्रदेश में सक्रिय रूप से दौरा करे और भाजपा को आगामी चुनाव में हराने के लिए संघर्ष करे।

कांग्रेस से राज्यसभा के लिए ये नेता दावेदार

पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एससी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के अलावा करीब एक दर्जन नेता राज्यसभा जाने के लिए प्रयासरत हैं।

दिग्विजय और जीतू कर चुके हैं इनकार- पूर्व सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राज्यसभा की रेस से खुद को अलग कर चुके हैं।

प्रदेश में हीटवेव की दस्तक, रतलाम में 40 पार

इंदौर, भोपाल-उज्जैन संभाग में असर ज्यादा, मौसम विभाग की घर में रहने की सलाह

भोपाल (नप्र)। मौसमी उथल-पुथल और चक्रवाती हवाओं का दौर थमते ही गर्मी बढ़ने लगी है। एकदम से तापमान में उछाल आया है। बीते तीन दिन में पारा करीब 5 डिग्री उछलकर 40 डिग्री के पार निकल गया है। रतलाम में 40.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा नर्मदापुरम, धार, बैरसिया, बड़वानी, विदिशा और खरगोन भी सबसे गर्म शहर बने हैं, जहां 39.0 डिग्री से अधिक तापमान है।

मध्य प्रदेश में अप्रैल के आखिर तक दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अलर्ट दिया गया है। मई-जून के जैसी गर्मी एमपी में इसी महीने देखने को मिलेगी। सूरज की सीधी धूप, रेगिस्तानी हवाएं और वायुमंडलीय प्रभाव मिलकर इलाके को जमकर तपाएंगे। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी भी जारी की है। बता दें कि बीते मार्च के आखिर में ही प्रदेश का पारा 41 डिग्री को छू रहा था। बीच में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से ठंडक बनी थी, लेकिन अब आसमान एकदम साफ होने से गर्मी रौद्र रूप दिखाएगी।

पचमढ़ी और कटनी सबसे ठंडे- मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पमचढ़ी फिलहाल सबसे ठंडा है। यहां न्यूनतम पारा 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कटनी में 14.1डिग्री पारा रहा है। इसके अलावा कल्याणपुर-शहडोल में 15.2 डिग्री, अमरकंटक 15.8 डिग्री और राजगढ़ में 16.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। यह प्रदेश के सबसे ठंडे शहर हैं। जबकि रतलाम और नर्मदापुर सबसे गर्म शहर में शामिल हैं।

डॉ. अरूण शर्मा, मौसम वैज्ञानिक, भोपाल ने कहा प्रदेश में अगले पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा। पारा बढ़ेगा, लू की आशंका भी बन सकती है। संभव हो तो 12 से 3 बजे तक दोपहर में बाहर निकलने से बचें

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कब निकलेगा स्थायी डीजीपी का आदेश ?

छत्तीसगढ़ के स्थायी डीजीपी का आदेश एक पहेली बन गया है। बताते हैं संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य के स्थायी डीजीपी के लिए 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम और 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया है। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को इन दोनों में से एक को चुनना है। यूपीएससी की चिट्ठी के बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए हलचल शुरू हुई, पर एक हफ्ते बाद भी शीर्ष स्तर पर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। कहते हैं स्थायी डीजीपी पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेना है, इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा की भी बड़ी भूमिका होगी। खबर है कि अदृश्य शक्ति के दबाव में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का मामला लटका पड़ा है। अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बने एक साल से ज्यादा समय हो गया है। वे जुलाई 2027 में रिटायर हो जाएंगे। जानकारों का कहना है कि अरुणदेव की नियुक्ति में एक पेंच फंस रहा है डीजीपी के कार्यकाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक् डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो साल होना चाहिए। अब अरुणदेव गौतम को डीजीपी बनाते हैं तो प्रभारी डीजीपी की अवधि को भी कार्यकाल माना जाय या फिर जब से स्थायी डीजीपी बनेंगे तब से दो साल कार्यकाल मिलेगा। स्थायी डीजीपी के मामले में लेटलतीफी समस्या बन गई है।

भाजपा के दुखी विधायक

कहते हैं अदृश्य और खुलेआम विरोध करने वालों को पार्टी में महत्व और सरकार में पद मिलने से भाजपा के कुछ विधायक इन दिनों बड़े दुखी और अपने को असहाय समझने लगे हैं। चर्चा है कि रायपुर संभाग के एक विधायक का 2023 के चुनाव में विरोध करने वाले दो नेताओं को पार्टी ने सत्ता में भागीदार बना दिया है। इससे विधायक जी बड़े दुखी हैं। विधायक जी भाजपा के जड़ से पैदा होने वाले नेता नहीं हैं। वे हवाई लेंडिग वाले नेता हैं, इस कारण भी उन्हें कड़वा घूंट पीने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। बताते हैं सत्ता में भागीदार बने दोनों नेता भी कोई भाजपा के जड़ वाले नहीं हैं, पर विधायक से पहले पार्टी से जुड़े हैं और टिकट के बड़े दावेदार थे। नए-नवेले के उम्मीदवार बनाया जाना दोनों को ही नहीं भाया था। अब दोनों को पद मिलना विधायक जी को नहीं भा रहा है। एक विधायक अपने छद्म विद्रोहियों से इतने दुखी हो गए कि मंच से ही उनके लिए आग उगलने लगे। अब भाजपा के बड़े नेता दुखी विधायकों के आंसू किस तरह पोछते हैं, देखना होगा।

डीजी के तीन पद बनाए जाने की चर्चा

कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक के तीन नए पद सृजित किए जाने की जुगत चल रही है। अभी राज्य में डीजी के चार पद हैं। एक्स कैडर तीन पद बन जाएंगे,तो सात डीजी हो जाएंगे। यह अलग बात है कि सरकार पिछले एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक डीजी को कोई काम नहीं दे पाई है और बिना काम के ही लाखों रुपए खर्च कर रही है। डीजी के चार पदों में अरुणदेव गौतम, पवनदेव, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता पदस्थ हैं। इनमें अरुणदेव गौतम प्रभारी डीजीपी हैं। बताते हैं 1994 बैच के एसआरपी कल्लूरी,1995 बैच के प्रदीप गुप्ता और 1996 बैच के विवेकानंद सिन्हा को डीजी बनाने के लिए पद सृजित करने की बात चल रही है। 1994 बैच के जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता डीजी हैं। एसआरपी कल्लूरी छूटे हैं। भारत सरकार की मंजूरी पर भी मामला निर्भर है। डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में भारत सरकार की अनुमति के बिना राज्य सरकार ने मुकेश गुप्ता और आर के विज को स्पेशल डीजी बना दिया गया था। कहा जाता है भारत सरकार की आपत्ति के बाद दोनों को फिर एडीजी बनाना पड़ा था ।

मक्सी कुजूर क्यों पिछड़ गए ?

चर्चा का विषय है कि दौड़ में आगे रहने के बाद भी चीफ इंजीनियर मक्सी कुजूर प्रभारी प्रमुख अभियंता क्यों नहीं बन पाए और शंकर ठाकुर की लाटरी लग गई। शंकर ठाकुर 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। तीन महीने के लिए प्रभारी ईएनसी बने शंकर ठाकुर का नाम वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर है। इसके बाद मक्सी कुजूर का नाम है। बताते हैं कि प्रभारी ईएनसी की दौड़ में चीफ इंजीनियर सतीश कुमार टीकम भी शामिल हो गए थे। टीकम को एक भाजपा विधायक का संबंधी बताया जाता है। वरिष्ठता सूची में टीकम का नाम सबसे नीचे है। विवाद में पड़ने की जगह सबसे वरिष्ठ चीफ इंजीनियर को प्रभारी ईएनसी बना दिया गया। मक्सी कुजूर मंत्रालय में जल संसाधन विभाग में ओएसडी थे, उन्हें फिलहाल महानदी परियोजना का चीफ इंजीनियर बना दिया गया है। मक्सी कुजूर के मंत्रालय से बाहर जाने के बाद जल संसाधन विभाग में ओएसडी का पद खाली हो गया है। ओएसडी पद पर कुछ एस ई और ई ई नजरें गड़ाए हुए हैं , अब देखते हैं किसका नंबर लगता है।

डीजीपी के आदेश से चल रहा पुलिस महकमा

रायपुर ग्रामीण,गरियाबंद,कोंडागांव और जांजगीर-चांपा जिलों में कामचलाऊ एसपी की पोस्टिंग प्रभारी डीजीपी के आदेश से ही हो गया। यहां पदस्थ प्रमोटी आईपीएस कार्यमुक्त होकर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चले गए। बताते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने चारों जिलों में तदर्थ एसपी की पोस्टिंग और वहां कार्यरत एसपी को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन की तरफ से अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव गृह सचिव से गृह मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री तक जाएगी। सुनते हैं कि फाइलों को ऑनलाइन निपटाने की व्यवस्था के बाद भी निर्णय में विलंब को देखते प्रभारी डीजीपी ने अपने तरफ से आदेश जारी कर खानापूर्ति कर दी। आमतौर पर जिलों में पोस्टिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर होती है। प्रभारी डीजीपी के आदेश पर चार जिलों में एसपी की पोस्टिंग की मंत्रालय और पुलिस महकमें में बड़ी चर्चा है और इसे नई प्रथा का आगाज बताया जा रहा है।

तीन मंत्री खुफ़िया एजेंसियों की निगाह में

कहते हैं राज्य के तीन मंत्री अलग-अलग कारणों से केंद्रीय खुफ़िया एजेंसियों की निगाह में चढ़ गए हैं। तीनों मंत्रियों की रिपोर्ट भाजपा हाईकमान को भेज दी गई है। कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों के विभागों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की भारी शिकायतें हैं। माना जा रहा है कि पांच राज्यों के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में इन तीनों मंत्रियों का विभाग बदल सकता है या फिर उनको ड्राप भी किया जा सकता है। अब देखते क्या होता है, पर एक बात तो साफ़ है कि मंत्रियों के पीछे कई आँख लगी हुई हैं।

हिमंता मामले में छग का एक कांग्रेस नेता सुर्ख़ियों में

कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पासपोर्ट मामले में छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस नेता भी सुर्ख़ियों में हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा फिलहाल उलझे हुए हैं। भले ही उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से कुछ दिनों की राहत मिल गई है। बताते हैं छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस नेता ने पवन खेड़ा के प्रेस कांफ्रेंस लेने से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म में इस मामले में खबर डाला था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता पर आंच आती है या फिर पाक साफ़ बच जाते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेसी नेता पहले भी सुर्ख़ियों में रहे हैं।